नई दिल्ली
07
सितंबर, 2026
सोमवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 158

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

शेफाली वर्मा को आउट कर फातिमा सना ने दिखाई अकड़ 07

संक्षिप्त वार्ता

इसरो में निजीकरण की आहट: कर्मचारियों ने पत्र लिख पूछा- हम कहां जाएंगे

वेब वार्ता, श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कर्मचारियों में अपने भविष्य और संगठन के निजीकरण को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के छह साल बाद, इसरो के अलग-अलग केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ प्रमुख कर्मचारी संघों ने एक संयुक्त पत्र लिखकर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है। यह पत्र 4 सितंबर को इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन को भेजा गया, जिसमें निजीकरण की नीति, भूमिका और मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ने वाले असर पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है।

कर्मचारी संघों की इस तीखी प्रतिक्रिया की मुख्य वजह इन-स्पेस के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका का हालिया बयान है। गोयनका ने एक कार्यक्रम में कहा था कि आखिरकार इसरो किसी भी लॉन्च व्हीकल (रॉकेट) का निर्माण नहीं करेगा। यह पूरा काम निजी क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।

3 लाख घरों में नहीं होगी पानी की कमी

जबलपुर। इस बार की बारिश न सिर्फ किसानों के लिए राहत लेकर आई, बल्कि शहर की बड़ी आबादी में गहराया जलसंकट भी दूर किया है। करीब एक चौथाई से ज्यादा आबादी की जलापूर्ति का आधार शहर के परियट और खंदारी जलाशय भी पानी से लबालब हो गए हैं। इसका सीधा असर जलापूर्ति पर पड़ा है। करीब तीन लाख घरों में अब दोनों टाइम पूर्व की तरह पर्याप्त जलापूर्ति होने लगी है।

इन जलाशयों का पानी कम होने से शहर की बड़ी आबादी करीब तीन माह तक पेयजल संकट से जूझ रही थी। दो की जगह एक टाइम जलापूर्ति की जा रही थी। वहीं अमृत 2.0 योजना से हो रहे काम के चलते अगले गर्मी के सीजन में भी जलसंकट से राहत की उम्मीद है।

मुंबई में दही हांडी का धूम: 50 फीट ऊपर महिला गोविंदाओं का बेजोड़ प्रदर्शन

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इस बार दही हांडी उत्सव को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह दिखा रहा है। यह पर्व अब सिर्फ भक्ति और रोमांच का नहीं, बल्कि लाखों रुपये के भारी-भरकम पुरस्कारों का भी एक बड़ा खेल बन गया है, जिसने गोविंदा पथकों के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। शहर के कोने-कोने में गोविंदा टोलियां मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी तोड़ने के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं।

इस वर्ष के उत्सव की बेहद खास और प्रेरणादायक तस्वीर मुंबई के दादर से सामने आई, जहां एक महिला गोविंदा पथक ने अद्भुत प्रदर्शन किया। करीब 50 फीट की ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को महिला टोली ने शानदार तालमेल दिखाकर मात्र पांच में मानव पिरामिड बनाकर फोड़ दिया। यह दृश्य अविश्वसनीय था और यह देखकर पूरा इलाका गोविंदा रे गोपाला के जयकारों से गूंज उठा। महिला गोविंदाओं की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि उन्होंने न केवल एक कठिन लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि इस पारंपरिक खेल में अपनी ताकत और कौशल का लोहा मनवाया।

स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया। अब स्वतंत्र भारद्वाज को सोमवार को नामित एससी/एसटी अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। यह मामला जुलाई में हुए सीजेपी प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट से जुड़ा है। गिरफ्तारी के बाद उनके वकीलों ने पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता पीयूष जैन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में एक बार फिर गुपचुप तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया। एक अन्य अधिवक्ता उमेश शर्मा ने भारद्वाज की जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखकर अदालत में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दलील दी जाएगी और इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जाएगा।

दिल्ली- एनसीआर में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी मालवाहक वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर बैन

वेब वार्ता, नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और व्यावसायिक वाहनों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्ष 2025 में दिल्ली में बिके कुल नए हल्के मालवाहकों (एन वन श्रेणी) में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी लगभग सात प्रतिशत तक पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली में 14,712 नए हल्के मालवाहक वाहन बिके, जिनमें से 13,646 सीएनजी और 1,026 इलेक्ट्रिक वाहन थे, जबकि डीजल के 35 और पेट्रोल के महज चार वाहन बिके। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में एन वन श्रेणी के वाहनों की संख्या 1.06 लाख हो गई है, जिसमें 1.03 लाख सीएनजी और 1,980 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर हुए 3 अधिकारी निलंबित, 1 को किया मुख्यालय अटैच

सागर जिले की बंडा तहसील में नकली शराब से हुई मौतों के मामले में सख्त कदम

वेब वार्ता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले की बंडा तहसील के तीन गांवों में नकली शराब पीने से कुछ लोगों की मौतों के मामलों मे सख्त एक्शन लिया है। उनके निर्देश पर तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक अधिकारी को मुख्यालय अटैच किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार, 6 सितंबर की सुबह ही कह दिया था कि इस घटना के लिए दोषी किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।

यह घटना सागर जिले के बंडा तहसील के ग्राम गोगरा खुर्द, नौरोज, और पाटन में हुई। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश

पर प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हुए सागर की सहायक आबकारी आयुक्त कीर्ति दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते और बंडा वृत्त के आबकारी उप-निरीक्षक प्रोशनी उरेती को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में समान रूप से जिम्मेदार मानते हुए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रभावित परिजन से मिला अधिकारी दल

उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को जिले से हटाकर ग्वालियर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिखाई सख्ती

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह संवेदनशील मामला है नई दिल्ली प्रवास के दौरान यह मामला संज्ञान में आते ही मैंने सागर जिले के प्रभारी मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में तत्काल जांच, राहत और उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके फलस्वरूप सागर संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अधिकारी दल ने प्रभावित परिजन से भी मुलाकात की थी। अधिकारी दल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपचार और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

दिनेश शर्मा अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल बने

यूपी की राजनीति में भाजपा का ब्राह्मण दांव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन वे उपराज्यपाल पद का कार्यभार संभालेंगे। 62 वर्षीय दिनेश शर्मा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होना था। ऐसे में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें यह संवैधानिक जिम्मेदारी दिया जाना राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उन्होंने 2017 से 2022 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान उनके पास माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। राजनीति में आने से पहले, दिनेश शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वे दो बार लखनऊ के महापौर भी रह चुके हैं, पहली बार 2008 में और फिर 2012 में। संगठन में भी उनका कद लगातार बढ़ता गया, 2014 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और वे भाजपा के गुजरात प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। साल 2023 में उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था।

डॉ. शर्मा की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल, यानी 2027 की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि इस नियुक्ति को केवल प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। बीजेपी ने हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश को लेकर अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को जगह मिली है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने और अलग-अलग सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। दिनेश शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और यूपी बीजेपी में वे लंबे समय से इस समुदाय के प्रमुख चेहरों में गिने जाते रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को यूपी के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने पारंपरिक सवर्ण आधार को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ अन्य सामाजिक समूहों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी के संगठनात्मक फैसलों में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को लेकर हाल के दिनों में चर्चा रही है।

शिक्षकों के सामने नई तकनीकी आफत, ई-अटेंडेंस ऐप पर मांगी जा रही सख्त लीगल अंडरटेकिंग

ग्वालियर। जिले के सरकारी स्कूलों में 95 प्रतिशत से अधिक शिक्षक वर्तमान में ई-अटेंडेंस और एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि अब शिक्षकों के सामने एक नई और गंभीर तकनीकी समस्या खड़ी हो गई है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 और उससे जुड़े हमारे शिक्षक व जीएफएमएस जैसे मोबाइल ऐप्स पर लॉगिन करते ही शिक्षकों से एक कड़े कानूनी घोषणा एवं डेटा गैर-प्रकटीकरण वचनबद्धता पत्र पर डिजिटल सहमति मांगी जा रही है।

इस अंडरटेकिंग की कठोर शर्तों ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे भविष्य में किसी भी डेटा लीकेज या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में पूरी जवाबदेही स्वयं शिक्षकों पर ही तय होने का खतरा बन गया है।

दिवाली पर घर जाने वालों को झटका, खिड़की खुलते ही ट्रेनें फुल, कई में रिग्रेट

वेब वार्ता, कानपुर

दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर अपने घर लौटने की योजना बना रहे रेल यात्रियों के लिए सफर की राह बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। एडवांस टिकट बुकिंग विंडो खुलते ही लंबी दूरी की अधिकतर ट्रेनों में उपलब्ध सीटें मिनटों में समाप्त हो गईं। विशेष रूप से कानपुर से गोरखपुर, पटना और हावड़ा रूट पर जाने वाली ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) बन गई है, जबकि कुछ प्रमुख ट्रेनों में तो बुकिंग ही बंद ('रिग्रेट') हो चुकी है।

इस बार धनतेरस और दीपावली के त्योहार को देखते हुए मुख्य तारीखों के आसपास यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया है। यात्री त्योहार से एक-दो दिन पहले गंतव्य तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर टिकट बुक करा रहे हैं, जिससे नियमित और प्रीमियम ट्रेनों की लगभग सभी श्रेणियों में सीट हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया है। कानपुर होकर पूर्वोत्तर व पूर्वी भारत की ओर जाने वाली तेजस और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा मांग कहीं अधिक है।

इसरो के नॉटी बॉय से चीन-पाक बेचैन? भारत के लिए कैसे यह गेमचेंजर

भारत ने अपनी नई सैटेलाइट ईओएस-05 का सफल प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

यह कोई सामान्य या नियमित उपग्रह प्रक्षेपण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर है जिसे समझना बेहद आवश्यक है। इस मिशन में नॉटी बॉय के नाम से पहचाने जाने वाले रॉकेट ने अपनी पिछली सभी शरारतों को पीछे छोड़ते हुए बेहद सटीक प्रदर्शन किया। यह नॉटी बॉय दरअसल उस रॉकेट का वैज्ञानिक उपनाम है जो पृथ्वी से उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। पहले यह रॉकेट अपने निर्धारित पथ से भटक जाता था, जिससे वैज्ञानिकों ने इसे यह अनौपचारिक नाम दिया था। लेकिन इस बार इसने सैटेलाइट को ठीक उसी ऊँचाई और स्थान पर सफलतापूर्वक पहुँचाया जहाँ उसे स्थापित होना था, जिससे वैज्ञानिकों में आत्मविश्वास और संतोष बढ़ा है कि इसमें किए गए तकनीकी बदलाव पूरी तरह से कामयाब रहे हैं।

यह नई सैटेलाइट, ईओएस-05, अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह) श्रृंखला का पाँचवाँ उपग्रह है। अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट का मुख्य कार्य पृथ्वी पर लगातार निगरानी रखना है, लेकिन ईओएस -05 एक सामान्य निगरानी उपग्रह से कहीं अधिक खास है। यह सैटेलाइट जियोस्टेशनरी श्रेणी की है। जियोस्टेशनरी का अर्थ है कि यह अंतरिक्ष में एक ही स्थान पर स्थिर खड़ी रहेगी और लगातार पृथ्वी की तस्वीरें और डेटा भेजती रहेगी। सामान्य उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए तस्वीरें भेजते हैं, जिससे किसी एक स्थान की अगली तस्वीर के लिए उन्हें अपना अगला चक्कर पूरा करने का इंतजार करना पड़ता है। इसके विपरीत, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ही बिंदु पर निरंतर निगरानी बनाए रख सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्थिर कैमरा लगातार फुटेज रिकॉर्ड करता है।

...और अधिक सशक्त स्थान दिलाता है

कल्पना कीजिए, यदि कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ में कोई बिल्डिंग बह रही हो, तो सामान्य सैटेलाइट केवल उसकी पहले और बाद की तस्वीरें ही दे पाती है। लेकिन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट उस घटना को लगातार रिकॉर्ड कर सकती है, जिससे यह देखा जा सकता है कि कैसे और कब वह बिल्डिंग पानी में बही। इस तरह की क्षमता भारत को निगरानी, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, रक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व बढ़त देगी। यह न केवल भारत की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगी बल्कि पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर भी निरंतर और विस्तृत नजर रखने में सहायक होगी। इस उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नया अध्याय जुड़ा है, जो देश को वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों की पंक्ति में और अधिक सशक्त स्थान दिलाता है।

झारखंड के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हार्ट अटैक से निधन

गिरिडीह में आज होगा अंतिम संस्कार, दो दिनों का राजकीय शोक घोषित

गिरिडीह/रांची। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात अचानक निधन हो गया। वे गिरिडीह स्थित अपने आवास पर थे। रात में सोने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तुरंत गिरिडीह के निजी मर्सी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद सुबह करीब 4 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके निधन पर राज्य सरकार ने दो दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है।

इलाज करने वाले डॉक्टर शहजाद शेख के अनुसार, मंत्री सुदिव्य सोनू को रात लगभग 2:15 बजे अस्पताल लाया गया था। उन्हें पिछले दो घंटे से सीने में तेज दर्द की शिकायत थी, अस्पताल पहुंचने पर उन्हें उल्टी हुई, जो उनके फेफड़ों में चली गई थी। डॉक्टरों ने तत्काल सांस की नली साफ कर ईसीजी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से हार्ट अटैक के लक्षण दिखे। अत्यधिक कम बीपी और गिरती स्थिति के बीच डॉक्टरों ने उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन 10 से 15 मिनट के भीतर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वे पहले से भी बीपी और शुगर की बीमारी से ग्रस्त थे।

बिहार के आरा में महानंदा एक्सप्रेस डिरेल: टला बड़ा हादसा

दिल्ली-हावड़ा रूट प्रभावित; स्टेशन मैनेजर सस्पेंड, गलत सिग्नल बनी वजह

वेब वार्ता, आरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय-दानापुर रेलखंड पर आरा रेलवे स्टेशन के पास रविवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा टल गया।

अलीपुरद्वार जंक्शन से दिल्ली जा रही 15483 महानंदा एक्सप्रेस की दो बोगियां (एक जनरल/एसएलआर और एक एसी/एच-1) पटरी से उतर गईं। सुबह करीब 4:12 बजे हुई इस घटना से यात्रियों और रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद स्टेशन मैनेजर एनके राय को निलंबित

कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची थी और इसे दिल्ली की ओर रवाना होना था। परिचालन के दौरान तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन को गलती से सासाराम लाइन का सिग्नल मिल गया। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, स्टेशन से महज 200 मीटर दूर (पोल संख्या 593/9अ के पास) अप लाइन पर इसके पहिए पटरी से नीचे उतर गए।

वंदे भारत और गरीब रथ समेत कई ट्रेनें लेट

3.5 घंटे बाद ट्रेन रवाना, दिल्ली-हावड़ा रूट बाधित

हादसे के बाद रेलवे की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए यात्रियों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचाया। इसके बाद डिरेल हुई बोगियों को काटकर अलग किया गया और दूसरे इंजन की मदद से ट्रेन को रिवर्स कर सुबह करीब साढ़े 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस हादसे के कारण दिल्ली-हावड़ा मुख्य मार्ग प्रभावित हुआ, जिससे वंदे भारत, विभूति एक्सप्रेस, गरीब रथ, इंटरसिटी और कैपिटल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से चलीं। कार्रवाई के दायरे में आए निलंबित स्टेशन मैनेजर एनके राय ने बताया कि सुबह 4:20 बजे सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। दोनों बोगियों के दो-दो पहिए पटरी से उतरे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया हादसा गलत सिग्नल मिलने की वजह से हुआ है, हालांकि पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल रेलवे अधिकारियों द्वारा तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

भारत ने यूएन में इक्वल अर्थ नक्शे का किया समर्थन

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन वाले विश्व मानचित्र संबंधी प्रस्ताव पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर इसके समर्थन में मतदान किया है। भारत ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य महाद्वीपों और भू-भागों के वास्तविक क्षेत्रफल को सही अनुपात में दिखाना है, जिससे दुनिया के क्षेत्रों को अधिक निष्पक्ष तरीके से दिखाया जा सके। हालांकि, भारत ने कहा कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा उसका रुख पूरी तरह स्पष्ट और अटूट है, और उसकी सीमाओं का कोई भी भ्रामक चित्रण स्वीकार्य नहीं होगा।

संपादकीय

वास्तविकताओं से दूर-1

विधानसभा का मानसून सत्र इस लिहाज से अलग रहा कि यहां इसकी-उसकी बहस में मुद्दों का यथार्थ तपा और कई प्रश्नों के जवाब में वास्तविकताओं को मंजूरी मिल गई। यहां सरकार के कड़े फैसले अगर यथार्थ समझा पाए, तो विपक्ष की निगरानी ने सरकार से वास्तविकता उगलवा ली। कुछ विधेयक इस दिशा में प्रदेश के सच की गवाही दे रहे हैं, तो कुछ फैसलों की निगाह से विपक्ष ने सुरमा चुरा लिया। हो हल्ला जहां हुआ, वहां विजनेस के मायने दोनों पक्षों में इतने बंटे कि सत्र अपने आप में स्पष्टीकरण बन गया। सरकार ने माना कि 3315 सिंग्ल टीचर स्कूलों के अस्तित्व के लिए नीति लाने की जरूरत है। सरकारी बसों का लेखा जोखा और इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार पर एक सार्थक बहस हुई, तो सरकार ने माना कि जरूरत के अनुसार नई बसें खरीदी जाएंगी। यहां सरकार के संकल्प दर्ज हुए तो राज्य की रफ्तार में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें आएंगी और कोशिश यह कि दो सौ हाइड्रोजन बसों का प्रयोग किया जाएगा। सरकारी विश्वविद्यालयों के भर्ती नियमों के टकराव पर सियासत के गिले-शिकवे एकतरफ, मगर यहां लोक सेवा आयोग या सरकारी एजेंसी के माध्यम से शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग के कर्मचारी नियुक्त होंगे। सत्र में घोषणाओं पर बजी तालियों का यथार्थ भी सामने आया। कई सालों से हम सुनते आए हैं कि प्रदेश में रज्जु मार्गों का जाल बुना जा रहा है और राजधानी शिमला में ट्रैफिक ट्रांजिट सिस्टम के तहत एक व्यापक योजना के तहत रज्जु मार्ग परियोजना का श्रीगणेश हो रहा है, लेकिन सत्र ने स्पष्ट कर दिया कि इनके लिए निजी निवेश की जरूरत है।

सरकार पीपी मोड के तहत रज्जु मार्गों की स्थापना पर रजामंद है। ऐसे में पी पी पी मोड के तहत पलचान-रोहतांग, चिंतपूर्णी मंदिर, बिजली महादेव, बाबा बालक नाथ, कुल्लू-ढालपुर रोप वे तथा नड्डी न्यू प्वाइंट धर्मशाला जिपलाइन परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यह हकीकत है कि अब सरकार को विकास के दायित्व में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश चाहिए। सराकर ने केंद्र के रवैये का यथार्थ भी बार-बार विपक्ष के सामने रखा, इसलिए हर उल्लेख आया गया नहीं है। खास तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पन्द्रह सौ रुपए की आपदा राहत राशि का रास्ता जिस ईमानदारी से हिमाचल से जुड़ना था, नहीं जुड़ा। इसी तरह विपक्ष ने हर प्रश्न के साथ वास्तविक स्थिति की परीक्षा ली मसलन 26724 आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य का सवाल, राज्य पर बढ़ते उधार की पैमाइश, हिमकेयर योजना के पेंडिंग 388 करोड़, आईपीएस-आईएएस अधिकारियों के पदों में कटौती तथा विभिन्न रिक्तियों पर यथार्थ खोजा गया। विपक्ष खेत तक गया और यूरिया की बोरी से नैनो यूरिया का बोझ हटवा दिया। मंदिरों के आय-व्यय का चि्ा खुला, तो सरकार ने इच्छा जाहिर की कि सामाजिक कार्यों में आस्था के स्रोत इस्तेमाल होंगे। सत्र की महिमा में बल्क ड्रग पार्क की वास्तविकता पूछी गई, तो पता चला कि आगामी मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश किस्मत की लाटरी खेलेगा, इसलिए इसे आर्थिक संसाधनों की खोज माना गया।

विधानसभा सत्र की खुश्की में राजनीति से ऊपर प्रदेश के महीन विषय भी उठे, तो जिक्र कांग्रेस की गारंटियों, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार और जलजीवन मिशन की बंद पड़ी 279 योजनाओं तक पहुंच गया। सरकार अब इस यथार्थ को स्वीकार कर चुकी है कि फैसले चाहे सख्त हों, लेकिन प्रदेश के भविष्य को रेखांकित जरूर करें। इसी दृष्टि से सडक अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2026 यह वादा कर रहा है कि सडकों पर न अतिक्रमण, न मलबा और न ही अनावश्यक पार्किंग बर्दाश्त होगी। समय का हर सूत्र हिमाचल में वास्तविकताओं के आधार पर फैसले लेने की गुजारिश जरूर कर रहा है।

दो टूक- कानून कठोर लेकिन बेटियां अब भी असुरक्षित क्यों?

दिल्ली-एनसीआर में एक स्लीपर बस के भीतर 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना हमारी सुरक्षा-व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन की निगरानी, पुलिसिंग और सामाजिक चेतना, चारों की एक साथ विफलता का आईना है। 4 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के परी चौक से एक नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर गलत जानकारी देकर स्लीपर बस में बैठाया गया और कश्मीरी गेट तक चालक तथा परिचालक पर उसके साथ यौन हिंसा करने का आरोप है। लगभग 47 किलोमीटर के इस सफर के बाद उसे कश्मीरी गेट के निकट रिंग रोड पर छोड़ दिया गया। इस घटना की सबसे भयावह बात केवल अपराध की क्रूरता नहीं बल्कि वह पूरा सुरक्षा-शून्य है, जिसमें यह अपराध संभव हुआ। एक नाबालिग लड़की रात में एक अनजान बस में बैठती है, बस लंबी दूरी तय करती है, उसके भीतर अपराध होता है और रास्ते में किसी स्तर पर ऐसी प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती, जो इस अपराध को रोक सके। रिपोर्टों के अनुसार बस में पर्दे लगे थे और सीसीटीवी की उपलब्धता को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं। यदि सार्वजनिक परिवहन के किसी वाहन का अंदरूनी हिस्सा इस तरह बाहरी निगरानी से लगभग कट जाए कि उसमें बैठे यात्रियों की सुरक्षा ही संदिग्ध हो जाए तो ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति देने वाली व्यवस्था से जवाब मांगना स्वाभाविक है।

यहां एक और असहज सवाल है कि घटना 4 अगस्त की बताई जा रही है लेकिन पुलिस ने इसकी जानकारी 31 अगस्त को सार्वजनिक की। इतने लंबे अंतराल में क्या हुआ? क्या जांच की गोपनीयता इसका कारण थी? क्या पीड़िता की निजता और सुरक्षा के कारण जानकारी सीमित रखी गई? या फिर किसी प्रशासनिक स्तर पर सूचना प्रबंधन में चूक हुई? इन प्रश्नों का स्पष्ट और विश्वसनीय उत्तर सार्वजनिक होना चाहिए क्योंकि अपराध की गंभीरता के साथ-साथ पुलिस की जवाबदेही भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। यह जरूर उल्लेखनीय है कि शिकायत मिलने के बाद कश्मीरी गेट पुलिस ने कार्रवाई की, सीसीटीवी के जरिए बस की पहचान की और आरोपित चालक-परिचालक को गिरफ्तार किया, बस भी बरामद कर ली गई यानी अपराध के बाद पुलिस की जांच क्षमता पर सवाल उठाने से पहले यह भी स्वीकार करना होगा कि अपराधियों तक पहुंचने में तकनीकी निगरानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन असली कसौटी गिरफ्तारी के बाद शुरू होती है। पुलिस का काम केवल अपराध होने के बाद अपराधी पकड़ना नहीं है, आधुनिक पुलिसिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अपराध होने से पहले उसे रोकना है। यदि सीसीटीवी अपराध के बाद बस का पता लगा सकता है तो सवाल यह है कि वही तकनीक संदिग्ध गतिविधि को पहले क्यों नहीं पकड़ सकी?

निर्भया कांड के बाद देश ने यही माना था कि अब व्यवस्था बदलेगी। दिसंबर 2012 में 23 वर्षीय युवती के साथ चलती बस में हुई बर्बरता ने पूरे देश को आंदोलित किया। कानून कठोर हुए, यौन अपराधों की कानूनी परिभाषाएं विस्तृत हुई, नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए अलग कानूनी ढांचा मजबूत हुआ और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा के सवाल को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया गया। निर्भया मामले के चार दोषियों को 2020 में फांसी दी गई लेकिन 13 वर्ष बाद यदि एक नाबालिग लड़की फिर चलती बस में ऐसी ही दरिंदगी का शिकार होती है तो यह सवाल पूछना जरूरी है कि हमने कानून तो बदल दिए लेकिन व्यवस्था कितनी बदली? कानून की कठोरता जरूरी है लेकिन कानून का डर केवल सजा की कठोरता से पैदा नहीं होता। अपराधी के मन में सबसे बड़ा भय पकड़े जाने की निश्चितता का होता है। यदि उसे लगता है कि वह रात के अंधेरे में, सुनसान रास्ते पर, निगरानी से बाहर किसी वाहन में अपराध कर सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा तो कानून की किताब में लिखी कठोरतम सजा भी तत्काल निवारक शक्ति नहीं बन पाती। इसलिए चुनौती केवल कठोर कानून की नहीं, निश्चित निगरानी, त्वरित गिरफ्तारी और समयबद्ध न्याय की है।

दिल्ली और नोएडा पुलिस के बीच घटना को लेकर सामने आए कथित विरोधाभास भी चिंता बढ़ाते हैं। दिल्ली-एनसीआर आज एक ऐसा महानगरीय क्षेत्र है, जहां शहरों की सीमाएं आम नागरिक के लिए लगभग अदृश्य हैं लेकिन अपराध होने पर वही सीमाएं पुलिस के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न बन जाती हैं। यदि कोई लड़की नोएडा में बस में चढ़ती है, दिल्ली की ओर आती है और दिल्ली में उतारी जाती है तो पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच वास्तविक समय में समन्वय क्यों नहीं हो सकता? इस घटना का एक और पहलू सार्वजनिक परिवहन की जवाबदेही से जुड़ा है। स्लीपर बसों में पर्दों का इस्तेमाल, वाहन के भीतर निगरानी, यात्रियों की पहचान, ड्राइवर-परिचालक का सत्यापन, निर्धारित मार्ग से विचलन, रात में अकेले या नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा, इन सभी बिंदुओं पर नियम होने भर से काम नहीं चलेगा। नियमों का वास्तविक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। परिवहन विभाग, पुलिस और बस संचालकों की संयुक्त जवाबदेही तय करनी होगी। ऐसी बसों का नियमित सुरक्षा ऑडिट हो, सीसीटीवी और आपातकालीन अलर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से काम करे, चालक-परिचालक का सत्यापन हो और उल्लंघन पर केवल जुर्माना नहीं, परमिट और संचालन अधिकार पर भी कठोर कार्रवाई हो।

हालांकि हम इस घटना को केवल पुलिस की विफलता कहकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। एक ओर 16 वर्ष की बच्ची रात में अकेले यात्रा करते हुए अपराधियों के निशाने पर आ जाती है और दूसरी ओर उम्रदराज महिलाएं अपने ही परिवारों द्वारा छोड़ दी जाती हैं। प्रश्न केवल कानून का नहीं है, प्रश्न उस सामाजिक मानस का है, जिसमें कमजोर व्यक्ति सबसे आसान लक्ष्य बन जाता है। जब परिवार में संवेदना कमजोर होती है, जब शक्ति को सम्मान और अपराधी प्रवृत्ति को प्रभाव समझा जाने लगता है, जब धन और बाहुबल सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनने लगते हैं, तब कानून अकेला समाज को नहीं बचा सकता। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अपराध के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। विपक्ष सरकार को घेरता है, सत्ता पक्ष गिरफ्तारी को अपनी उपलब्धि बताता है और बहस कुछ दिनों बाद किसी दूसरे मुद्दे में दब जाती है लेकिन पीड़िता का भय, उसका भविष्य और उसके मन पर पड़ा आघात किसी राजनीतिक बयान से समाप्त नहीं होता। महिला सुरक्षा चुनावी नारा नहीं, शासन की बुनियादी कसौटी होनी चाहिए।

ह्यमहिलाएं रात में कितनी सुरक्षित हैंह्न जैसे सवालों का उत्तर विज्ञापनों या राजनीतिक दावों से नहीं दिया जा सकता। उत्तर सड़कों पर दिखना चाहिए, बसों में दिखना चाहिए, पुलिस की प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए और उन व्यवस्थाओं में दिखना चाहिए, जो किसी अकेली लड़की को संकट में पड़ने से पहले सुरक्षा उपलब्ध कराएं। वर्तमान घटना से दिल्ली-एनसीआर के लिए कुछ स्पष्ट सबक निकलते हैं। रात में चलने वाली बसों की अनिवार्य निगरानी हो, सभी स्लीपर बसों में कार्यशील सीसीटीवी और आपातकालीन संचार प्रणाली हो। चालक-परिचालक के पुलिस सत्यापन और प्रशिक्षण को नियमित किया जाए, बस के निर्धारित मार्ग और ठहराव की डिजिटल निगरानी हो, नाबालिग या अकेली महिला यात्री के साथ संदिग्ध स्थिति में चालक दल को विशेष प्रोटोकॉल का पालन करना पड़े, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस के बीच साझा रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित हो। सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी महिला या बच्ची की शिकायत को ह्यक्षेत्राधिकारह्न के नाम पर एक थाने से दूसरे थाने तक न दौड़ाया जाए।

निर्भया के बाद हमने बहुत कुछ बदला लेकिन शायद उतना नहीं, जितना बदलना चाहिए था। कठोर कानून बनाना आसान है लेकिन कानून को जमीन पर उतारना कठिन। सीसीटीवी लगाना आसान है; उसे चौबीस घंटे सक्रिय रखना कठिन। पुलिस वाहन खड़े करना आसान है, वास्तविक गश्त सुनिश्चित करना कठिन। महिला सुरक्षा के दावे करना आसान है लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाना कठिन, जिसमें कोई लड़की रात के अंधेरे में अकेली होने के बावजूद असुरक्षित महसूस न करे। इसलिए इस घटना को केवल एक और अपराध मानकर भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। यह चेतावनी है कि अपराधी तभी बेखौफ होते हैं, जब व्यवस्था में कहीं न कहीं भय का अभाव पैदा हो जाता है। उन्हें कानून से नहीं, कानून के निश्चित और निष्पक्ष क्रियान्वयन से डरना होगा। समाज को भी यह तय करना होगा कि वह अपराध के बाद मोमबत्ती जलाने वाला समाज बनेगा या अपराध से पहले अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला समाज।

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ह्यसागर से अंतरिक्ष तक : भारत की रक्षा क्रांतिह्न सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)

प्रमाणित होती अर्थव्यवस्था की मजबूती

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 31 अगस्त को पहली तिमाही के वृद्धि दर के आंकड़े सामने आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अकादमिक जगत के एक वर्ग ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय आय और जीडीपी की गणना की पद्धति में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनकी वजह से इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह होता है। इसकी पड़ताल आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण और निरंतर उपलब्ध आर्थिक संकेतकों का मजबूत आधार है। ये संकेतक अर्थव्यवस्था के विस्तार की मजबूती को प्रमाणित करते हैं। जैसे वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह माल ढुलाई और कारोबारी मांग में मजबूती का संकेत देती है। कंपनियां भविष्य में मांग बढ़ने की उम्मीद में वाहनों के बेड़े का विस्तार कर रही हैं। निवेश के मोर्चे पर भी काफी मजबूती दिखाई दे रही है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मशीनरी और उपकरणों के आयात में 51.5 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई।

सीमेंट उत्पादन, तैयार स्टील की खपत और बुनियादी ढांचे तथा निर्माण से जुड़ी वस्तुओं के उत्पादन में भी मजबूत वृद्धि हुई। ई-वे बिल बनने की संख्या में भी दोहरे अंकों में वृद्धि जारी रही। जीएसटी की दरों में बड़े स्तर पर बदलाव और युक्तिसंगत बनाने के बाद सकल जीएसटी संग्रह में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन सभी संकेतकों को एक साथ देखने से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और आर्थिक वृद्धि का आधार काफी व्यापक है। पहली तिमाही में वाहनों की जोरदार बिक्री से संकेत मिलता है कि अपनी पसंद और आवश्यकता पर खर्च करने को लेकर लोगों की क्षमता बढ़ी है, जिसने मांग को मजबूती प्रदान की है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तीनों में बैंक ऋण की व्यापक वृद्धि हुई है। मजबूत निवेश, स्थिर खपत, माल ढुलाई में तेजी और बैंक ऋण के विस्तार का एक साथ होना इसका संकेत है कि अर्थव्यवस्था का यह विस्तार टिकाऊ है।

वृद्धि को लेकर संदेह का एक पहलू मौजूदा कीमतों और स्थिर कीमतों पर जीडीपी के बीच कीमतों में किए जाने वाले समायोजन यानी जीडीपी डिफ्लेशन को लेकर है। यह चिंता तब भी बनी हुई है, जबकि आधार वर्ष में बदलाव के दौरान गणना की पद्धति में काफी सुधार किए गए हैं। पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद जीडीपी डिफ्लेटर को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सवाल उठाया गया है, वह भी इसी मुद्दे से जुड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली बेहतर पद्धतियों के अनुरूप संशोधित राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में कीमतों के समायोजन के लिए अब थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआइ की जगह नए उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी पीपीआइ का उपयोग किया गया है। हालांकि, डिफ्लेशन की पद्धति और कीमतों से जुड़े आंकड़ों के स्रोत दोनों में एक साथ बदलाव किए जाने के कारण हाल में जीडीपी डिफ्लेटर में आए बदलावों को समझना कुछ मुश्किल हो गया है। पहली तिमाही के आंकड़े जारी होने के बाद हुई चचाओं में भी यह बात सामने आई है।

हमने विनिर्माण क्षेत्र में ह्यडबल डिफ्लेशनह्न पद्धति अपनाई है। इसमें उत्पादन और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं (मध्यवर्ती खपत) की कीमतों में बदलाव को अलग-अलग समायोजित किया जाता है। इसके बाद दोनों के वास्तविक मूल्यों के अंतर से वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में यह दुनिया भर में अपनाई जाने वाली सबसे बेहतर पद्धति मानी जाती है। जब उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें तैयार उत्पादों की कीमतों से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, तो मौजूदा कीमतों पर जीवीए की वृद्धि वास्तविक जीवीए की वृद्धि से कम हो सकती है। जब उत्पादन और कच्चे माल, दोनों की कीमतें बढ़ रही हों, तब भी जीवीए का निहित डिफ्लेटर नकारात्मक हो सकता है।

विकसित देशों में भी डबल डिफ्लेशन पद्धति अपनाने पर इस तरह के परिणाम सामने आए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी तैयार उत्पादों की कीमतों की तुलना में अधिक रही। इससे जीवीए डिफ्लेटर कम हुआ। इसके अलावा, कुछ सेवा क्षेत्रों में कीमतों में बहुत कम वृद्धि होने के कारण जीवीए डिफ्लेटर और सामान्य सीपीआइ और डब्ल्यूपीआइ के बीच अंतर और बढ़ गया। स्थिर कीमतों पर जीवीए का अनुमान सामान्य या समग्र मूल्य सूचकांकों के आधार पर नहीं लगाया जाता। इसके लिए अलग-अलग प्रकार के उत्पादन और उसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के लिए 300 से अधिक उत्पादक मूल्य और अन्य मूल्य सूचकांकों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अलग-अलग और व्यापक स्तर के कुछ आंकड़ों को सामने रखकर इन जीवीए अनुमानों पर सवाल उठाना उचित नहीं। इससे एक ऐसी सांख्यिकीय व्यवस्था को लेकर जनता में गलत धारणा बन सकती है, जिसे अधिक पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधार किया गया है। एक अध्ययन में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की पद्धति पर अनुचित तरीके से सवाल उठाए गए हैं। इसमें यह मान लिया गया है कि जीडीपी वृद्धि को कथित रूप से जरूरत से ज्यादा दिखाए जाने के कारण भारत के वास्तविक प्रदर्शन और इस काल्पनिक तुलना वाले देश के प्रदर्शन के बीच जो अंतर निकाला गया है, वह वास्तव में "निचली सीमा" है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जीडीपी की गणना की पद्धति में आखिर गलती कहां है। आर्थिक आकलन की किसी प्रणाली की आलोचना स्वागतयोग्य है, क्योंकि इससे सुधार की दिशा स्पष्ट हो सकती है, लेकिन भ्रामक टिप्पणियों और सुविधाजनक निष्कर्षों से यह संभव नहीं होता। विशेष तौर से तब जब अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्र तेजी का संकेत कर रहे हों।

एस. महेंद्र देव और सौरभ गर्ग

(देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सौरभ गर्ग सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं। आलेख में मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार एंटनी साइरिएक का भी योगदान है)

आइआइटी संस्थानों में क्यों सुसाइड कर रहे हैं होनहार?

देश के प्रतिष्ठित आईआईटी व आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों की झड़ी लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर के आईआईटी में पांच वर्षों में 70 होनहारों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जबकि जुलाई से शुरू नए सत्र में अब तक आईआईटी में तीन व आईआईएम में एक सुसाइड की वारदात सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट बताती है कि आईआईएससी बंगलूरू में भी 15 दिन में दो छात्रों ने खुदकशी की है।

आपको बता दें कि भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामले एक बेहद गंभीर और संवेदनशील चिंता का विषय बन चुके हैं। हाल ही में, 22 अगस्त 2026 को आईआईटी दिल्ली के एमएससी भौतिकी के 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार ने परिसर की एक इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद संस्थान में छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।यह स्थिति केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शीर्ष इंजीनियरिंग परिसरों में मानसिक तनाव और शैक्षणिक दबाव की गहरी समस्याओं को उजागर करती है।हालिया प्रमुख घटनाएं और आंकड़ेआईआईटी दिल्ली ऋषिकेश कुमार की मृत्यु के बाद, छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर फ्लैश मार्च निकाला और कक्षाओं का बहिष्कार किया। छात्रों का आरोप है कि ऋषिकेश मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और उन्हें प्रशासन से आवश्यक सहयोग व हॉस्टल सुविधा नहीं मिली। पिछले 30 महीनों में इस संस्थान में यह आठवीं आत्महत्या है।वर्ष 2026 की शुरूआत (जनवरी) में पीएचडी स्कॉलर राम स्वरूप ईश्वरम ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे पहले दो हफ्तों के भीतर ही परिसर में एक और छात्र जय सिंह मीना की मौत हुई थी। इस संस्थान ने भी पिछले दो वर्षों में कई ऐसी दुखद घटनाएं देखी हैं। अगस्त 2026 में आईआईटी खड़गपुर के भी एक छात्र की परिसर में ऊंचाई से गिरने से मौत हुई। रिपोर्टों के अनुसार, देश के शीर्ष 11 आईआईटी में पिछले 5 सालों में 35 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें आईआईटी मद्रास, हैदराबाद और दिल्ली सबसे आगे रहे हैं।

विभिन्न जांच समितियों, शिक्षाविदों और स्वयं छात्रों के अनुसार इन आत्महत्याओं के पीछे जो कारण रेखांकित किए गए हैं उनमें शैक्षणिक दबाव कड़ा पाठ्यक्रम, लगातार परीक्षाएं, ग्रेडिंग सिस्टम और असाइनमेंट का अत्यधिक बोझ छात्रों को मानसिक रूप से थका देता है।भविष्य और करियर की चिंता के चलते छात्र छात्राओं में अवसाद घर कर जाता है। प्लेसमेंट न होना, इंटर्नशिप के अवसरों से वंचित होना या रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आने वाली अड़चनें छात्रों में भारी अनिश्चितता पैदा करती हैं।सामाजिक अलगाव एक बड़ा कारण है कई छात्र अपने परिवारों से दूर रहने, कड़ी प्रतिस्पर्धा और संवाद की कमी के कारण अकेलेपन और अवसाद का शिकार हो जाते हैं।प्रशासनिक और सुपरवाइजर का व्यवहार भी इन घटनाओं के लिए लिए जिम्मेदार है विशेषकर पीएचडी और मास्टर्स के छात्रों में यह देखा गया है कि गाइड या प्रशासन के कथित असंवेदनशील रवैये या अत्यधिक नियंत्रण के कारण छात्र खुद को असहाय महसूस करते हैं।जातिगत या लैंगिक भेदभाव से भी इस तरह की वारदातों की तादाद कम नहीं हो रही है। कुछ मामलों में वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों ने भेदभाव या पूर्वाग्रहों का सामना करने की बात भी उठाई है।

आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली में 30 महीनों में आठवें छात्र की आत्महत्या की खबर ने एक बार फिर देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों के अंदरूनी अस्वस्थता को सामने ला दिया है। यह महज एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि व्यवस्थागत विफलता का प्रतीक है। जब एक संस्थान, जिसे देश की उच्च मेधा को तराशने का केंद्र माना जाता है,वहां आए दिन युवा छात्रों द्वारा सुसाइड की वारदात बेहद संवेदनशील और असामान्य स्थिति का हवाला देती है। इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा आत्मघाती माहौल शिक्षण संस्थानों में कैसे पनप रहा है? कई मामलों में अवसाद, परीक्षा में असफलता का डर और समय रहते काउंसलिंग नहीं मिलना प्रमुख कारण बताए गए हैं। छात्रों का आरोप है कि घटना के बाद प्रशासन का रवैया अक्सर औपचारिक शोक संदेश तक सीमित रह जाता है। एक छात्र की मौत के बाद परिसर सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही दोहराव छात्रों में गुस्सा और निराशा पैदा कर रहा है। हालिया घटना के बाद सैकड़ों छात्रों का प्रदर्शन, डीन और एसोसिएट डीन के इस्तीफे की मांग, स्वतंत्र जांच और परिवार को मुआवजे की मांग, ये सब इस गुस्से की अभिव्यक्ति हैं। प्रशासन का दावा है कि काउंसलिंग सेवाएं, २४ घंटे मानसिक स्वास्थ्य सहायता और पाठ्यक्रम में लचीलापन उपलब्ध हैं। यदि ऐसा है तो हालात इतना खराब क्यों बने हैं कि आए दिन छात्र जान दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स भी इस मुद्दे पर काम कर रही है। लेकिन रिपोर्ट और कमेटियां तब तक अनुपयोगी हैं, जब तक उनकी सिफारिशें जमीनी स्तर पर लागू न किया जाए । सरकार को इस ओर तत्काल प्रभाव से गंभीरता से कारवाई करनी चाहिए। देश के होनहार छात्र इस तरह जान गंवाने के लिए नहीं है। हर मौत पूरे परिवार को तोड़ देती है वही समाज खासकर उचच शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा और गरिमा पर भी सवालिया निशान लगा रहीं हैं। हालांकि बताना जरूरी है कि सरकारी स्तर से संकट को देखते हुए छात्र संगठनों की मांगों के बाद कई कदम उठाए गए हैं। आईआईटी दिल्ली मामले की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बाहरी समिति का गठन किया गया है, जिसमें एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख और छात्र प्रतिनिधि भी शामिल हैं।पाठ्यक्रम में लचीलापन लाया गया है। संस्थानों ने शैक्षणिक भार कम करने, पहले सेमेस्टर में क्रेडिट कम करने और वीकेंड परीक्षाओं को सीमित करने जैसे नीतिगत बदलाव शुरू किए हैं।मानसिक स्वास्थ्य सहायता परिसरों में 24/7 काउंसलिंग हेल्पलाइन, वेलनेस सेंटर और मेंटरशिप प्रोग्राम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि समय रहते मानसिक संकट से जूझ रहे छात्रों की पहचान की जा सके।छात्रों और उनके परिजनों का भी कर्तव्य है कि वह अपने परिवार या परिचित छात्र छात्राओं के सम्पर्क में रहें कोई अवसाद या असामान्य बात का आभास मिलते ही संस्थान को अवगत कराएं ताकि समय पर काउंसलिंग कर छात्र को आत्मघाती होने से बचाया जा सके।

लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

क्या मायावती फिर बन सकती हैं किंगमेकर?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट भले अभी दूर दिखाई देती हो, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्तारूढ़ भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम दल अपने-अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने में जुट गए हैं। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता और उनके लगातार सामने आ रहे बयान खासे महत्वपूर्ण हो गए हैं।

मायावती का यह स्पष्ट संकेत कि बसपा आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े करता है। क्या यह केवल पार्टी की स्वतंत्र पहचान बचाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी चुनावी रणनीति है? क्या मायावती अपने पुराने दलित जनाधार को फिर से एकजुट कर सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल—क्या बसपा सत्ता में वापसी भले न कर पाए, लेकिन चुनाव परिणामों को प्रभावित कर एक बार फिर 'किंगमेकरइ की भूमिका में आ सकती है ?इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन मायावती की राजनीति को केवल उनके बयानों के आधार पर समझना भी उचित नहीं होगा। उनके हर राजनीतिक कदम के पीछे उत्तर प्रदेश के जटिल सामाजिक समीकरण और चुनावी गणित को समझना जरूरी है।

बसपा कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे मजबूत ताकतों में रही है। दलित मतदाताओं के मजबूत आधार पर खड़ी इस पार्टी ने समय के साथ अपनी रणनीति का विस्तार किया और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखायइ के नारे के साथ दलित-ब्राह्मण सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ने का सफल प्रयोग किया। इसी सामाजिक इंजीनियरिंग के सहारे मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन पिछले एक दशक में बसपा का चुनावी प्रभाव लगातार कमजोर हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकी। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव मायावती के लिए सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि बसपा के राजनीतिक प्रभाव को पुनर्जीवित करने की निर्णायक परीक्षा है।

अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। गठबंधन की राजनीति के अनुभवों से मायावती कई बार असंतोष जाहिर कर चुकी हैं। बसपा नेतृत्व की चिंता यह भी है कि गठबंधन की स्थिति में उसका मूल मतदाता दूसरे दलों की ओर खिसक सकता है। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने पर पार्टी अपने उम्मीदवारों, अपने चुनाव चिन्ह और अपने मुद्दों के साथ मतदाताओं तक पहुंच सकती है।

हालांकि यह रणनीति जोखिम से भी भरी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कुछ प्रतिशत वोटों का अंतर दर्जनों सीटों के परिणाम बदल सकता है। यदि बसपा अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को पर्याप्त रूप से अपने साथ बनाए रखने में सफल होती है, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में वह भाजपा और सपा के बीच मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। यही वह बिंदु है जहां मायावती की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बसपा यदि सत्ता की दौड़ में सीधे तौर पर आगे नहीं भी आती, लेकिन पर्याप्त सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती है तो सरकार बनाने की स्थिति में उसका समर्थन या विरोध निर्णायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में मायावती फिर से 'किंगमेकरइ की भूमिका में दिखाई दे सकती हैं।लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने पुराने जनाधार को बचाना होगा।

बसपा की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती दलित मतदाताओं के बीच अपने प्रभाव को पुनर्जीवित करना है। दलित समाज अब पहले जैसा एकरूप राजनीतिक समूह नहीं है। नई पीढ़ी के मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान, सुरक्षा, सरकारी योजनाओं का लाभ और आर्थिक अवसर जैसे मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।इसलिए केवल पुराने नारों और भावनात्मक अपील के सहारे बसपा की वापसी आसान नहीं होगी। मायावती को यह बताना होगा कि आज के उत्तर प्रदेश के लिए बसपा का वैकल्पिक विकास मॉडल क्या है और सत्ता में आने पर आम नागरिक को उससे क्या हासिल होगा।यही कारण है कि पार्टी की नजर अब केवल अपने पारंपरिक दलित आधार पर नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे सामाजिक समूहों पर भी है। यदि बसपा ओबीसी, गैर-जाटव दलित, मुस्लिम और सवर्ण समाज के कुछ हिस्सों में प्रभाव बढ़ाने में सफल होती है तो उसका चुनावी प्रभाव काफी बढ़ सकता है।

अतीत में दलित-ब्राह्मण सामाजिक समीकरण बसपा के लिए बेहद सफल रहा था। लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भाजपा का अपना मजबूत सामाजिक आधार है, समाजवादी पार्टी पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रही है और विभिन्न छोटे दल भी जातीय समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में मायावती के लिए पुराने सामाजिक समीकरणों को हूबहू दोहराना संभव नहीं होगा। उन्हें नए सामाजिक गठजोड़ की तलाश करनी होगी।

इसके साथ संगठन भी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव केवल नेता के बयानों से नहीं जीते जाते। बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता और मतदाताओं से लगातार संपर्क किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक ताकत होते हैं। पिछले कुछ चुनावों में बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर उतना सक्रिय दिखाई नहीं दिया, जितना उसके राजनीतिक प्रभाव के दौर में हुआ करता था। मायावती को अब बयानबाजी से आगे बढ़कर संगठन को चुनावी मशीनरी में बदलना होगा। कार्यकताओं में उत्साह पैदा करना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक संघर्ष को फिर से मजबूत करने के लिए मैदान में है। आकाश आनंद से जुड़े संगठनात्मक और नेतृत्व संबंधी घटनाक्रम भी इसी व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। यदि बसपा को भविष्य की पार्टी बनना है तो उसे नेतृत्व की अगली पीढ़ी को लेकर स्पष्टता पैदा करनी होगी। मायावती का राजनीतिक नियंत्रण अभी निर्विवाद हो सकता है, लेकिन लंबे समय की राजनीति के लिए संगठन में स्थायी और भरोसेमंद नेतृत्व संरचना आवश्यक होगी। नेतृत्व को लेकर असमंजस का असर कार्यकताओं के मनोबल और चुनावी तैयारी पर पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती को अपनी राजनीति को प्रतिक्रियात्मक राजनीति से निकालकर सकारात्मक एजेंडे की ओर ले जाना होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, छोटे कारोबारियों की कठिनाइयां और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बसपा को स्पष्ट और विश्वसनीय नीति प्रस्तुत करनी होगी।

उत्तर प्रदेश की जनता केवल जातीय समीकरणों के आधार पर मतदान नहीं करती। सामाजिक पहचान महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास और व्यक्तिगत आकांक्षाएं भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। विशेष रूप से युवा मतदाता राजनीतिक दलों से भविष्य की स्पष्ट तस्वीर चाहता है।

यही मायावती के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि वह अपने पुराने दलित आधार को मजबूती से वापस जोड़ लेती हैं और उसके साथ ओबीसी तथा अन्य सामाजिक वर्गों में भी स्वीकार्यता बढ़ा लेती हैं, तो बसपा का चुनावी प्रभाव अचानक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा और सपा दोनों के लिए बसपा को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा।

लेकिन यदि बसपा अपने पुराने वोट आधार को भी पूरी तरह नहीं बचा पाती और संगठन जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं बनता, तो अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पार्टी के लिए उलटा नुकसान भी साबित हो सकती है।

इसलिए 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम सपा का मुकाबला नहीं होगा। इसके बीच बसपा का प्रदर्शन कई क्षेत्रों में चुनाव की दिशा तय कर सकता है। मायावती सत्ता की सीधी दावेदार बनें या न बनें, लेकिन यदि वह पर्याप्त सीटों पर मजबूत स्थिति में पहुंचती हैं तो सरकार बनाने के गणित में उनकी भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो सकती है।

फिलहाल मायावती की सक्रियता को हल्के में लेना राजनीतिक भूल होगी। उनके सामने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का कठिन लक्ष्य है। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बचाने की कोशिश है, सामाजिक समीकरणों पर जोर आधार बढ़ाने की रणनीति है और संगठन को मजबूत करने की कवायद चुनावी प्रभाव वापस पाने का प्रयास। अब असली सवाल यह नहीं है कि मायावती बयान दे रही हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या उनकी बयानबाजी जमीन पर राजनीतिक संगठन और जनसमर्थन में बदल पाएगी ?उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसे दौर आए हैं जब किसी दल को कमजोर समझा गया और उसने चुनावी परिणामों में अप्रत्याशित प्रभाव डाला। बसपा के पास भी अपना राजनीतिक इतिहास, मजबूत कैडर और एक विशिष्ट सामाजिक आधार है। यदि मायावती इन ताकतों को फिर से सक्रिय करने में सफल होती हैं, तो 2027 का चुनाव उनके लिए राजनीतिक पुनर्जन्म का अवसर बन सकता है। इसलिए फिलहाल मायावती को केवल सत्ता की दावेदार के रूप में नहीं, बल्कि संभावित 'किंगमेकरइ के रूप में देखना अधिक उचित होगा। चुनावी राजनीति में अंतिम फैसला जनता करती है, लेकिन इतना तय है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा।

सौरभ वार्ष्णेय

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

संक्षिप्त वार्ता

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को स्कूलों में रहेगा अवकाश

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के स्कूल 11 सितंबर को बंद रहेंगे। आधिकारिक परिपत्र में यह जानकारी दी गई। पांच सितंबर को जारी परिपत्र में कहा गया कि यह अवकाश शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों पर लागू होगा, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल शामिल हैं।

शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय भी इस दिन बंद रहेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा में कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को शालीमार बाग विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित बीबी-ब्लॉक की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। वहीं, विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एएफ-ब्लॉक में खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग के सीएंडडी ब्लॉक की मेन रोड पर खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्य का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

दिल्ली-एनसीआर में वर्षा होने से निचले इलाकों में भारी जलभराव

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। यहां लगातार बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई कॉलोनियों और निचले इलाकों में जलभराव के कारण घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे भारी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बारिश शनिवार को दिनभर रुक-रुक कर जारी रही। इसके चलते आईटीओ, आश्रम, धौला कुआं, रिंग रोड, विकास मार्ग और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया। निचले इलाकों खासकर सीमापुरी, संगम विहार, बादली, मयूर विहार फेज-3 और नजफगढ़ के कई क्षेत्रों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। जलभराव के खतरे को देखते हुए प्रशासन को एहतियातन कई प्रमुख अंडरपास पर बैरिकेडिंग कर यातायात बदलना पड़ा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।

एटीएम तोड़ने वाला शातिर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। क्राइम ब्रांच ने एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इमरान के रूप में हुई है। 20 से अधिक मामलों में शामिल रहे बदमाश को बुधवार को मेवात से पकड़ा गया। आरोपी छह मामलों में भगोड़ा घोषित है। डीसीपी चंदर कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि एसीपी उमेश बरथवाल की टीम एटीएम चोरी के मामलों की जांच कर रही थी। इन सभी मामलों में इमरान उर्फ इम्मा नाम सामने आया था। वह राजधानी में एटीएम चोरी के 12 मामलों में शामिल था। उसके खिलाफ अन्य राज्यों में आठ एफआईआर दर्ज हैं। डीसीपी ने बताया कि पुलिस एक साल से इमरान की तलाश कर रही थी।

24वीं एशियाई कराटे चैंपियनशिप

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का भारतीय दल 24वीं कैडेट, जूनियर एवं अंडर-21 एशियन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जॉर्डन पहुंच गया है। यह प्रतियोगिता जॉर्डन के अम्मान शहर में 11 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। दल का नेतृत्व कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भरत भूषण शर्मा और महासचिव संजीव कुमार जांगड़ा कर रहे हैं। टीम के साथ मैनेजर और कोच अनिकेत गुप्ता भी मौजूद हैं। मुख्य कोच कीर्तन कोंडरू के साथ वैलेना वेलेंटीना, दीपिका धीमान और नरेश मुदावथ भी कोच के रूप में शामिल हैं। इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व 34 खिलाड़ी कर रहे हैं।

ब्रिक्स इंडिया 2026: दुनिया का स्वागत करने को तैयार नई दिल्ली, एनडीएमसी के चेयरमैन ने शेयर की झलक

12 और 13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने राष्ट्रीय राजधानी की प्रमुख सड़कों, बाजारों, होटल क्षेत्रों और वीआईपी मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, रोशनी और यातायात मार्गों की सुगमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयारियों को तेज कर दिया है।

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

इस बीच, एनडीएमसी के चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तैयारियों को लेकर कुछ तस्वीरें और ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो शेयर किया है।

एक पोस्ट में उन्होंने ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो शेयर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ स्थानों पर एनडीएमसी द्वारा 2026 के ब्रिक्स समिट का स्वागत और स्मरण करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि हमारे गोलचक्करों पर रोशनी और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। इससे पहले न्यू दिल्ली मुंसिपल काउंसिल ऑफिशियल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ्ननई दिल्ली, दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, एनडीएमसी व्यापक सौंदर्यीकरण और सड़क सुधार कार्यों के माध्यम से नई दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों को एक नया और

जीवंत रूप दे रहा है। गड्ढों से मुक्त सड़कों, बेहतर फुटपाथों और स्पष्ट जेबरा क्रॉसिंग से लेकर थीम आधारित पेंटिंग, रोशन फव्वारों और उन्नत फुटपाथों तक, हर पहलू को सावधानीपूर्वक बेहतर बनाया जा रहा है ताकि एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक स्वागत योग्य शहर का निर्माण हो सके। नई दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों को गर्व, उद्देश्य और वैश्विक स्वागत की भावना के साथ रूपांतरित किया जा रहा है। इससे पहले एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि पालिका केंद्र स्थित एनडीएमसी का एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर 5 से 14 सितंबर तक चौबीसों घंटे काम करेगा। साथ ही, यातायात की निगरानी और कॉल अटेंड करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी मौजूद रहेगा।

समन्वय स्थापित करेंगे

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि प्रत्येक तीन शिफ्ट में निदेशक या संयुक्त निदेशक स्तर के दो अधिकारी तैनात रहेंगे, जबकि 11 विंगों को रात्रि ड्यूटी सौंपी गई है ताकि किसी भी समस्या का समय पर समाधान किया जा सके। अधिकारी ने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया है कि संबंधित विभाग के प्रभारी कॉल अटेंड करने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जबकि मुख्य सुरक्षा अधिकारी दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

फूलों के गमले शामिल हैं

धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लोधी रोड, तिलक मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, शांतिपथ और जाकिर हुसैन रोड सहित पांच स्थानों पर विशेष रूप से धुंध का छिड़काव किया जाएगा। तैयारियों में 17 प्रमुख गोल चक्करों, 11 होटलों और 10 एनडीएमसी भवनों पर सजावटी प्रकाश व्यवस्था के अलावा 15 स्थानों पर फूलों के बोर्ड, नौ स्थानों पर फूलों के फव्वारे और प्रमुख सड़कों और महत्वपूर्ण चौराहों के किनारे 15,000 से अधिक फूलों के गमले शामिल हैं।

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी

कई लोगों के फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिर गई, जिसमें मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह इमारत मोतीबाग इलाके में सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास गिरी।

दिल्ली फायर ब्रिगेड ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी दोपहर 1:30 बजे मिली। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 1:50 बजे स्टेशन ऑफिसर (एसटीओ) नरेंद्र घटनास्थल पर पहुंचे और सूचना दी कि एक इमारत गिर गई है और कुछ लोग उसके नीचे फंसे हुए हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की। इसके बाद, एक एसडब्ल्यूटी, एक बिग फायर टेंडर (बीएफटी), एक ऑफिसर-इन-चार्ज, डीओ मुकेश वर्मा और एसटीओ मनोज को घटनास्थल पर भेजा गया। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। फंसे हुए लोगों की संख्या की पुष्टि बाद में की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़

नौकरी दिलाने के बहाने ठगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने राजधानी के संगम विहार इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है।

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

पुलिस ने रविवार को बताया कि यह कॉल सेंटर नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार लोगों से कथित तौर पर धोखाधड़ी कर रहा था और पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की उम्र 19 से 30 साल के बीच है।

पुलिस के बयान के मुताबिक, 1 सितंबर को एएटीएस व नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम को संगम विहार के झरोदा माजरा में चल रहे एक संदिग्ध फर्जी कॉल सेंटर के बारे में गुप्त जानकारी मिली। इस कॉल सेंटर से नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार लोगों से धोखाधड़ी की जा रही थी। जानकारी की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने कॉल सेंटर पर छापा मारा। छापे के दौरान सतीश चंद्र मौर्य और दूसरे टेली-कॉलर कॉल सेंटर चलाते हुए पाए गए। तीन आरोपी नौकरी चाहने वालों से संपर्क करके और अलग-अलग झूठे बहाने बनाकर पैसे मांगते हुए, कथित तौर पर धोखाधड़ी वाला भर्ती का काम करते हुए पाए गए।

शुरूआती जांच से पता चला कि बेरोजगार उम्मीदवारों से संपर्क करके उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एनालिस्ट, वेब डिजाइनर और अकाउंटेंट जैसी नौकरियों का ऑफर दिया जाता था। बेरोजगारों को भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में पैसे देने के लिए उकसाया जाता था। फर्जी कॉल सेंटर से तलाशी के दौरान 9 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 7 डेबिट कार्ड, दो बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर लिखे तीन नोटपैड और 6,730 रुपये नकद बरामद हुए। आगे की जांच में पता चला कि आरोपी ह्यजॉब है सपोर्टह्न नाम के एक ऐप के जरिए नौकरी चाहने वालों की निजी जानकारी हासिल कर रहे थे। इस ऐप पर उम्मीदवार खुद को रजिस्टर करते थे और नौकरी के अलग-अलग मौकों के लिए अप्लाई करते थे। आरोपी खास तौर पर उन उम्मीदवारों को निशाना बनाते थे, जिन्होंने ह्यटाटा मोटर्सह्न में नौकरी के लिए अप्लाई किया था और फिर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े प्रतिनिधि बनकर उनसे संपर्क करते थे।

आरोपियों ने उम्मीदवारों को यह कहकर गुमराह किया कि भर्ती के अलग-अलग चरणों को पूरा करने के लिए कई तरह के पेमेंट जरूरी हैं और इस तरह झूठे बहाने बनाकर उनसे बार-बार पैसे जमा करवाए। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस टीम को इस धोखाधड़ी वाले भर्ती नेटवर्क में दो और आरोपियों के शामिल होने का पता चला। बाद में दोनों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी भूमिकाओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों को नामी कंपनियों में नौकरी का लालच देकर ठगने का एक व्यवस्थित तरीका अपनाया था। शुरूआत में संभावित उम्मीदवारों से संपर्क किया जाता था और उनसे कूरियर चार्ज के तौर पर 499 रुपये जमा करने को कहा जाता था। एक बार शुरूआती पेमेंट हो जाने के बाद आरोपी अलग-अलग झूठे बहाने बनाकर उनसे और पैसे वसूलते रहते थे।

आरोपी एक के बाद एक पेमेंट की मांग करके पीड़ितों को इस फर्जी भर्ती प्रक्रिया में उलझाए रखते थे। जब कोई पीड़ित और पैसे देने से मना कर देता या असमर्थता जताता तो आरोपी उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते और अचानक बातचीत बंद कर देते थे। पुलिस ने बताया कि अन्य साथियों की पहचान करने, पैसों के लेन-देन का पता लगाने और धोखाधड़ी के पूरे दायरे का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

द्वारका जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बिना वैध दस्तावेज के रह रही युगांडा की 2 महिला नागरिक गिरफ्तार

द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रही दो विदेशी महिला नागरिकों को पकड़ा है। पकड़ी गई दोनों महिलाएं युगांडा की नागरिक हैं और लंबे समय से वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रही थीं।

नई दिल्ली वेब वार्ता

पुलिस के अनुसार, द्वारका जिले के डीसीपी कुशल पाल सिंह, आईपीएस के निर्देश पर और एसीपी डाबड़ी के पर्यवेक्षण में विदेशियों के सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों का पता लगाना है जो अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और साथ ही उन विदेशियों की जांच करना है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी अभियान के तहत उत्तम नगर थाने के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम में एसआई जॉनी कुमार, हेड कॉन्स्टेबल विनोद और हेड कॉन्स्टेबल सुनीता शामिल थीं, जिन्होंने एसएचओ उत्तम नगर के नेतृत्व और एसीपी डाबड़ी के मार्गदर्शन में उत्तम नगर इलाके में विदेशी नागरिकों की जांच और सत्यापन का काम शुरू किया।

पुलिस टीम ने पहले स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई और तकनीकी निगरानी व मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर उत्तम नगर इलाके से दो विदेशी नागरिकों को पकड़ा। पकड़ी गई महिलाओं की पहचान डोरीन एम्पुरिरे और गोर्रेट अडोंग के रूप में हुई है और दोनों युगांडा की नागरिक हैं। गिरफ्तारी के बाद जब इन महिलाओं से विस्तार से पूछताछ की गई तो वे भारत में अपने रहने को लेकर कोई भी कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर पाईं। उनके पास न तो वैध वीजा था और न ही कोई अन्य दस्तावेज जिससे यह साबित हो सके कि वे कानूनी रूप से भारत में रह रही हैं। पूछताछ और सत्यापन के बाद दोनों विदेशी नागरिकों को दिल्ली के एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) के सामने पेश किया गया। एफआरआरओ कार्यालय द्वारा उचित सत्यापन के बाद दोनों को हिरासत केंद्र सेवा सदन, शहजादा बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई विदेशी नागरिकों के खिलाफ भारत में अवैध रूप से रहने के लिए कानून के अनुसार आगे की कानूनी और निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एनडीएमसी ने रात में सफाई के लिए 300 कर्मचारी तैनात किए

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 से पहले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और दुरुस्त करते हुए रात में करीब 300 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया है साथ ही, मशीनीकृत सफाई उपकरणों का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चार सितंबर से अतिरिक्त सफाई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत रात की पाली में करीब 300 सफाई कर्मचारियों के साथ 10 मैकेनिकल रोड स्वीपर (एमआरएस) की भी व्यवस्था की गई है।

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना का जागरूकता अभियान शुरू, मार्च 2027 तक चलेगा : सिरसा

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर और व्यापक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में प्रवर्तन, तकनीकी हस्तक्षेप, हितधारकों की भागीदारी और जनसहभागिता को समाहित किया गया है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक शहरव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) एवं जागरूकता अभियान शुरू किया है।

दिल्ली के जाफराबाद में अवैध शराब के गोदाम पर छापा, 1,576 क्वार्टर बरामद, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्पेशल स्टाफ/एनईडी की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,576 क्वार्टर बोतलें अवैध शराब बरामद की हैं। शराब की बरामद बोतलों पर केवल हरियाणा में बिक्री के लिए लिखा हुआ है।

पुलिस के अनुसार 4 और 5 सितंबर 2026 की दरम्यानी रात स्पेशल स्टाफ/एनईडी को सूचना मिली थी कि जफराबाद इलाके में एक गोदाम में अवैध शराब का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर एसीपी/ऑपरेशन्स की निगरानी में और इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, आईसी/स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने जाफराबाद स्थित सब्जी मंडी प्राइमरी स्कूल के पास जम्मू मोहल्ला में 158/2 नंबर के गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को गोदाम से 32 कार्टन मिले। इन कार्टनों की जांच करने पर इनमें कुल 1,576 क्वार्टर बोतलें बरामद हुईं। इन्हें दिल्ली में बेचने की योजना थी, जबकि शराब दिल्ली में बिक्री के लिए अधिकृत नहीं है। कार्रवाई के दौरान गोदाम के मालिक दीपक उर्फ छापा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की उम्र 28 वर्ष है और वह बाबरपुर (दिल्ली) का रहने वाला है। बरामद शराब को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मामले में जाफराबाद थाना पुलिस ने दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी शराब कहां से लाता था और इसे दिल्ली में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, दीपक उर्फ छापा के खिलाफ डकैती, चोरी, झपटमारी, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम से जुड़े 17 मामले दर्ज रहे हैं। पुलिस ने उसे थाना वेलकम का बैड कैरेक्टर भी बताया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अवैध शराब की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है।

धौला कुआं फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी भीषण आग, समय रहते फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली के धौलाकुआं फ्लाईओवर पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू-धूकर जलने लगा। घटना के बाद फ्लाईओवर पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन गई।

कार में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और लगभग पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने से आसपास के रास्तों को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरूआती जानकारी में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। आग कैसे लगी और घटना के समय कार में कितने लोग सवार थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

वहीं, इससे पहले 4 सितंबर को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके के खजूरी खास में शुक्रवार सुबह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक पोल्ट्री ट्रक डंपर के पिछले हिस्से से टकरा गया था।

टीमों को मौके पर बुलाया था

पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ था। इसके बाद खजूरी खास थाने में पीसीआर को कॉल मिली थी लेकिन पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पोल्ट्री लेकर जा रहा ट्रक डंपर के पीछे से टकराया था। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल्ट्री ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ट्रक चालक अंशुल क्षतिग्रस्त केबिन के अंदर फंस गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद दिल्ली फायर सर्विस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमों को मौके पर बुलाया गया था। टीमों ने कटिंग उपकरणों की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर अंशुल को बाहर निकाला था।

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस-3 में युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मयूर विहार फेस-3 इलाके में रविवार सुबह करीब 5:00 बजे अज्ञात लोगों ने लाठी और डंडों से पीटकर एक युवक की हत्या कर दी। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। हालांकि, घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदा लोगों की सूचियों से इसका मिलान किया जा रहा है।

गार्ड नंदलाल ने बताया कि वह सुबह करीब 4:00 बजे जब अपने बाथरूम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ युवक एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे थे। नंदलाल ने जब हिम्मत जुटाकर उन हमलावरों को

भगाने और बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया। हमलावरों ने गार्ड को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हें भी जान से मार देंगे। जान बचाने के डर से गार्ड तुरंत वहां से हटा और बिना देर किए पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को खंगाल रही है। घटनास्थल के आसपास और भागने वाले संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को पुलिस द्वारा बारीकी से खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावरों के चेहरों की पहचान की जा सके और उनके भागने की दिशा का पता चल सके।

पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच आपसी रंजिश, लूटपाट या किसी अन्य विवाद की ओर इशारा कर रही है, लेकिन असली वजह आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही साफ हो पाएगी। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि मृतक की शिनाख्त जल्द से जल्द की जा सके।

कछौना की जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग

वेबवार्ता/हरदोई । कछौना क्षेत्र की जर्जर और खराब सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कछौना के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष नवीन पटेल ने बालामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामपाल वर्मा को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों को त्वरित विकास योजना अथवा विधायक निधि से प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की मांग की।

मांग पत्र में कछौना एवं कोथावां विकासखंड की कुल 12 प्रमुख सड़कों और संपर्क मार्गों का उल्लेख किया गया है। इनमें कछौना-हरदोई मार्ग से महावीर प्रसाद महाविद्यालय कामीपुर तक इंटरलॉकिंग, बालामऊ-नारायन देव संपर्क मार्ग, भानपुर-रामपुर संपर्क मार्ग, समसपुर-महेशन मढ़िया मार्ग, बरौली-ढोली मार्ग, दीननगर बैरागी खेड़ा मार्ग से घनश्याम नगर पुलिया तक मार्ग, जब्बर खेड़ा से नहर पटरी तक मार्ग, बिलौनी संपर्क मार्ग से मक्का खेड़ा तक मार्ग, अरसेनी से आरखताली डामर रोड तक मार्ग, सोम डामर रोड से मुरारनगर महाकालेश्वर मंदिर तक मार्ग, सोम से गौसगंज रोड को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग तथा आरके इंडस्ट्रीज से मुन्ना साइकिल वाले के घर तक मार्ग शामिल हैं। नवीन पटेल ने कहा कि इन मार्गों के निर्माण से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और राहगीरों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विधायक से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई। इस दौरान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष डॉ. शिवराज सिंह पटेल, पूर्व महामंत्री शिवम मिश्रा, भाजपा नेता उमेश सिंह, अनूप सिंह, ग्राम प्रधान कप्तान गौहानी, सनोज राठौर, जनसरोकार मंच के संयोजक परमेश्वर दयाल गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

यूपी शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 17 डायट में नए प्रधानाचार्य किए तैनात

एटा, इटावा व मऊ को मिला अतिरिक्त प्रभार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के साथ शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को भी लगातार सुदृढ़ कर रही है।

वेब वार्ता, लखनऊ

इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार ने निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश को पत्र जारी कर 17 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में वरिष्ठ प्रवक्ताओं को वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रधानाचार्य पद का प्रभार दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एटा, इटावा और मऊ के डायट में तीन वरिष्ठ प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

विशेष सचिव की ओर से पत्र जारी

योगी सरकार के विशेष सचिव की ओर से जारी पत्र में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत डायटों के सुचारु संचालन के लिए संबंधित वरिष्ठ प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य पद का प्रभार दिए जाने का निर्णय बताया गया है। निदेशक एससीईआरटी को संबंधित अधिकारियों को प्रभार दिलाने और आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

डायट, प्रदेश की शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन, शैक्षणिक सहयोग और विद्यालयी शिक्षा में नवाचारों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में इन संस्थानों की अहम भूमिका है। ऐसे में डायटों को प्रभावी नेतृत्व उपलब्ध कराना शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

17 डायटों में वरिष्ठ प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी

शासन के निर्देश के अनुसार इनमें राजेश कुमार सिंह (बहराइच), राम प्रताप सिंह (श्रावस्ती), विनोद कुमार (हमीरपुर), मुक्तेश कुमार (फिरोजाबाद), संजय कुमार (फरुखाबाद), नवाब वर्मा (हाथरस), दीपक श्रीवास्तव (ललितपुर), अश्वनी प्रताप सिंह (जालौन), विश्वदीपक त्रिपाठी (चंदौली), विमलेश कुमार त्रिपाठी (मिजार्पुर), सुश्री रिद्धि पाण्डेय (सोनभद्र), सुनील कुमार (बलिया), कुलदीप नारायण सिंह (देवरिया), दीनानाथ (कुशीनगर), नरेन्द्र सिंह (संतकबीर नगर), आशीष चौहान (शाहजहांपुर) और नन्दित कुमार (झांसी) शामिल हैं।

इन्हें मिला अतिरिक्त प्रभार

जिन तीन वरिष्ठ प्रवक्ताओं/अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनमें पत्र में आराध्य उपाध्याय, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट अलीगढ़ को डायट एटा, अतुल कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा को डायट इटावा तथा अतुल कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट मऊ को डायट मऊ के प्रधानाचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

संक्षिप्त वार्ता

दुकान में चोरी के मामले में पेड़हथा निवासी विकास गिरफ्तार, दो टैबलेट बरामद

वेबवार्ता/हरदोई। थाना शाहाबाद पुलिस ने दुकान से नकदी और सामान चोरी के मामले में पेड़हथा निवासी विकास पुत्र श्रीपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए दो टैबलेट बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, 30 अगस्त 2026 को अल्हापुर सैदीखेड़ा निवासी अनुपम पुत्र रामकिशोर की दुकान से 17 हजार रुपये की नकदी और कुछ सामान चोरी हो गया था। मामले में पीड़ित की तहरीर पर एक सितंबर को थाना शाहाबाद में कौशल पुत्र दिनेश निवासी मोहल्ला जमाल खत्ता खां के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 583/26, धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान प्रकाश में आए आरोपी विकास पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम पेड़हथा, थाना शाहाबाद को पुलिस ने चोरी के दो टैबलेट सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, नामजद आरोपी कौशल की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अमरेश कुमार, कांस्टेबल रोबिन, कांस्टेबल शमशाद अहमद और कांस्टेबल अभिषेक शामिल रहे।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरी : पंकज सिंह

नोएडा, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। नंगला चरण दास गांव स्थित जूनियर हाईस्कूल में रविवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन नोएडा विधायक पंकज सिंह ने किया। फेलिक्स हॉस्पिटल की ओर से इसका आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा मिली। इस मौके पर पंकज सिंह ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई बार छोटी स्वास्थ्य समस्या के लिए भी अस्पताल तक जाना पड़ता है। ऐसे में उनके क्षेत्र में ही निशुल्क स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श उपलब्ध होना काफी उपयोगी है।

रामलीला के लिए भूमि पूजन 20 को होगा

नोएडा, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा होने वाली भव्य रामलीला के लिए 20 सितंबर को भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें शहर के गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। सनातन धर्म रामलीला समिति के चेयरमैन टीएन गोविल की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में रामलीला की तैयारियों पर चर्चा की गई। समिति के महासचिव संजय बाली ने बताया कि सेक्टर-21ए स्थित रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला को इस बार पिछले वर्षों से अधिक भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारी है। रामलीला मंचन करने वाली कमेटी और रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पूतलों के निर्माण के लिए टीम का चयन कर लिया गया है। बैठक में सुशील भारद्वाज, अल्पेश गर्ग, पंकज जिंदल, एससी गोयल, अतुम वर्मा, लोकेश कश्यप, अमित अग्रवाल, संजय जैन, आलोक कुमार अग्रवाल, सौरभ शर्मा, मुकेश शर्मा और राजीव गर्ग सहित समिति के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत

नोएडा, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। सेक्टर-63 में तेज रफ्तार कार के चालक ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कार लेकर भाग गया। सेक्टर-63 थाने की पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। एटा के मेहनी गांव निवासी सूरजपाल का 36 वर्षीय बेटा गजेंद्र सिंह नोएडा की चोटपुर कॉलोनी में किराये पर रहता था। वह सेक्टर-63 स्थित मोब्लैड मोड एंड एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड में सेमप्लिंग का काम करता था। गजेंद्र चार सितंबर की रात करीब आठ बजे ड्यूटी खत्म कर कंपनी से घर लौट रहा था। वह साइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से तेज गति में आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गजेंद्र सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक भाग गया, लेकिन कार की नंबर प्लेट का हिस्सा साइकिल में फंस गया। पुलिस के मुताबिक कार की नंबर प्लेट नोएडा की है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता सूरजपाल ने पांच सितंबर को सेक्टर-63 थाने में शिकायत देकर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

18 करोड़ की मरम्मत के बाद भी जामनी बांध में रिसाव, सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

किसानों ने पूछा-आखिर कहां गई मरम्मत की रकम? भाकियू टिकैत ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांगी उच्चस्तरीय जांच

ललितपुर/आलोक चतुर्वेदी

जामनी बांध में लगातार हो रहे पानी के रिसाव ने एक बार फिर बांध की सुरक्षा और सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों से रिसाव की समस्या बने रहने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं होने से किसानों और बांध के आसपास तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मरम्मत कार्यों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है।

भाकियू पदाधिकारियों ने तहसील अध्यक्ष धनसिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से जामनी बांध में हो रहे रिसाव का स्थायी समाधान कराने के साथ ही अब तक कराए गए मरम्मत कार्यों और उन पर खर्च की गई धनराशि की जांच कराने की मांग की गई।

किसान नेताओं का कहना है कि जामनी बांध में पिछले कई वर्षों से पानी के रिसाव की समस्या बनी हुई है। बरसात और बांध में पानी का स्तर बढ़ने के साथ रिसाव की समस्या को लेकर किसानों में भय का माहौल पैदा होता है। इसके बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया जा सका है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली और बांध की मरम्मत व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मरम्मत पर करोड़ों खर्च, फिर भी रिसाव बरकरार

भाकियू ने आरोप लगाया कि जामनी बांध की मरम्मत के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद यदि बांध से पानी का रिसाव जारी है तो यह गंभीर विषय है। किसान नेताओं ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? क्या मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की पर्याप्त निगरानी हुई या फिर केवल कागजी खानापूर्ति तक ही कार्य सीमित रह गए?

यूनियन ने मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृत धनराशि, वास्तविक खर्च, कराए गए कार्यों और कार्यदायी संस्था की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच किए जाने की बात कही गई है।

विशेषज्ञों की टीम से तकनीकी जांच की मांग

भाकियू ने मांग की है कि बांध की तकनीकी स्थिति की जांच विशेषज्ञों की टीम से कराई जाए, ताकि रिसाव की वास्तविक वजह सामने आ सके। किसानों का कहना है कि केवल समय-समय पर की जाने वाली अस्थायी मरम्मत से समस्या का समाधान नहीं होगा। बांध की संरचनात्मक मजबूती की जांच कराकर रिसाव का स्थायी उपचार कराया जाना जरूरी है।

किसान नेताओं ने कहा कि जामनी बांध केवल सिंचाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं, बल्कि इससे आसपास के किसानों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। ऐसे में बांध की सुरक्षा से जुड़े मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है।

शाहाबाद रोड पर महिला से मंगलसूत्र लूटने वाले दो शातिर गिरफ्तार, मंगलसूत्र व बाइक बरामद

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कोतवाली शहर पुलिस ने महिला से मंगलसूत्र लूटने के मामले का खुलासा करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र, लॉकेट तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, 31 अगस्त 2026 को रंजना पत्नी भैय्यालाल निवासी पकल्या, थाना हरपालपुर, बावन रोड स्थित कांजीवी हॉस्पिटल के पास पैदल जा रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने उनका मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

पुलिस ने मामले में सत्यम शुक्ला पुत्र हरिकिशोर निवासी भवानीपुर, थाना बख्शी का तालाब, लखनऊ और सुंदरलाल पुत्र बाबूलाल निवासी सुल्तानपुर, थाना इटौंजा, लखनऊ को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से एक मंगलसूत्र-लॉकेट और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

रामगंगा में नहीं फंसे गोवंश, एसडीएम ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की

वेबवार्ता/हरदोई। सोशल मीडिया पर प्रसारित नदी की बाढ़ में फंसे दो दर्जन गोवंश खबर के संबंध में उपजिलाधिकारी सवायजपुर शिवानी सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की है। एसडीएम के अनुसार रविवार को ग्राम बेडिजोर, परगना कटियारी, तहसील सवायजपुर में रामगंगा नदी पर बने पुल के आसपास गोवंशों के नदी के पानी में फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आसपास के ग्रामीण अपने पशुओं को चराने के लिए नदी क्षेत्र की ओर ले गए थे। गोवंश एवं अन्य पशु नदी के पानी से होकर सुरक्षित सूखे स्थान पर पहुंचकर घास चर रहे थे।

परिजन की डाँट से नाराज होकर गुम हुई 3 युवती को जीआरपी ने किया बरामद

वेब वार्ता, कानपुर। पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी० द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व मे आपरेशन मुस्कान के तहत सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सकुर्लेटिंग एरिया, टिकट घर, यात्री प्रतीक्षालय पर भ्रमण, चेकिंग के दौरान हरैया जनपद बस्ती के द्वारा सूचना दी गयी की ग्राम जमुनहा कला थाना हरैया जनपद बस्ती की तीन युवती रानी (18) (काल्पनिक) पुत्री बरसाती तारा (20) (काल्पनिक) पुत्री परशुराम व पिंकी 19 (काल्पनिक) पुत्री लालता प्रसाद निवासीगण ग्राम जमुनहा कला थाना हरैया जनपद बस्ती जो घर से नाराज होकर परिजन से बिना बतायें गुम हो गयी हैं, तथा यह आशंका है कि तीनो युवती बस्ती से दिल्ली की तरफ जा सकती है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल ओम नारायण सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एसआई मुकुन्दलाल यादव, क्यूआरटी टीम, सभी प्लेटफार्म ड्यूटी के साथ समस्त प्लेटफार्म, सकुर्लेटिंग एरिया, एफओबी, टिकटघर, ट्रेन मे डिटेल व हुलिया के आधार पर खोजबीन प्रारम्भ कि। करीब आधे घन्टे बाद तीनो युवतियों को प्लेटफार्म 4/5 पर बने बेंच पर बैठी मिली। फोटोग्राफ से पहचान कर उक्त तीनों युवती को समझा-बुझा कर थाना कार्यालय पर बने महिला हेल्पडेस्क पर बैठाया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना हरैया जनपद बस्ती व युवती के परिजन को दूरभाष से सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे युवतियों के परिजनों ने सभी की पहचान कर ली। थाना प्रभारी ने पहचान सुनिश्चित कराने के बाद सभी युवती को उनके परिजनों को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया। परिजनो द्वारा थाना जीआरपी पुलिस कानपुर सेन्ट्रल की इस सराहनीय कार्य के लिये भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया।

राष्ट्रीय एथलेटिक्स ऑफिशिएटिंग कार्यशाला दो अक्तूबर से

नई दिल्ली, 06 सितंबर (वेब वार्ता)। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीईएफआई) 2, 3 व 4 अक्तूबर को मैत्रेयी कॉलेज में ट्रैक एंड फील्ड लेवल-1 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसमें अधिकारियों, कोचों और शिक्षकों को एथलेटिक्स नियमों व ऑफिशिएटिंग से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

हरदोई एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण

आरटीओ ने दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) बस्ती, फरीदुदीन ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय हरदोई का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान आरटीओ ने कार्यालय के कामकाज और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारकी से जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय में उपस्थित आम जनता से बातचीत की और प्रत्येक पटल (काउंटर) पर जाकर पत्रावलियों व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, उनके स्टोरेज (संग्रहण क्षमता) और उपलब्धता की जांच की गई।

विस्तृत जानकारी दी गई

साथ ही, कार्यालय में तैनात अधिकारियों, नियमित कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के पहचान पत्रों (क्ऊ उं१२) का भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण के अंत में संभागीय परिवहन अधिकारी ने कार्यालय परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और सभी विभागीय अभिलेखों को पूरी तरह सुव्यवस्थित रखने के कड़े निर्देश जारी किए। इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन/प्रवर्तन द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई है।

विजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को दिया सत्यनिष्ठा व साइबर सुरक्षा का संदेश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। विजिलेंस जागरूकता अभियान-2026 के अंतर्गत आरसेटी हरदोई में प्रशिक्षुओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम के प्रति जागरूक करते हुए जिम्मेदार एवं सतर्क नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना रहा।

कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया के विजिलेंस अधिकारी रंजोध सिंह ने भ्रष्टाचार की रोकथाम, सत्यनिष्ठा के महत्व, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव, साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षुओं को बैंक खाते, एटीएम/डेबिट कार्ड, पासवर्ड, ओटीपी सहित अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी अनधिकृत व्यक्ति से साझा न करने के लिए सचेत किया।

कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के लिए चार्ट निर्माण एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें करीब 50 प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक जागरूकता, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव और सत्यनिष्ठा जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मकता व ज्ञान का प्रदर्शन किया।

आरसेटी हरदोई के निदेशक विक्रांत ओझा ने कहा कि ईमानदारी, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और पारदर्शिता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार की रोकथाम केवल किसी विभाग या संस्था की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अपनाने के लिये प्रेरित किया

कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सत्यनिष्ठा से समृद्धि का संदेश देते हुए व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

महत्वपूर्ण ख़बर

राजनीतिक रंग ले रहे युवाओं के आंदोलन, चुनाव की तैयारी करे बसपा

- लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने देश में जेन-जी और जेन-अल्फा के सामने खड़ी रोजगार जैसी ज्वलंत समस्याओं को लेकर गहरा दुख और चिंता जताई है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों के बीच से शुरू हुए आंदोलनों के राजनीतिक दलों के प्रभाव में आने की धारणा बन रही है, जिससे आंदोलन की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जंतर-मंतर पर हुए जेन-जी आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन अब इसका स्वतंत्र स्वरूप खत्म होकर राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है।

मायावती ने स्पष्ट किया कि युवाओं और छात्रों की वास्तविक तथा जायज मांगों के प्रति बसपा की हमेशा से सहानुभूति रही है। उन्होंने अपनी सभी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि पार्टी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करें और युवाओं की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए ज्ञापन सौंपें।

राजनीतिक रंग ले रहे युवाओं के आंदोलन, चुनाव की तैयारी करे बसपा

- रायपुर। गुढ़ियारी इलाके में नाबालिग बच्चों को डराने-धमकाने और उन्हें अपने झांसे में लेकर आभूषण व नकदी हासिल करने का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि वंदना साहू ने उसकी 11 वर्षीय भांजी रूपल साहू को डराकर उसके सोने के कान के झुमके और चेन ले लिए।

इसके बाद परिवार का रानी हार लाने के लिए भी बच्ची पर दबाव बनाया गया।

आर्कटिक की पिघलती बर्फ : रूस का नया समुद्री रास्ता, भारत भी शामिल, वैश्विक चिंताएं बढ़ीं

नई दिल्ली। आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से पिघलती बर्फ, जिसकी वजह आमतौर पर जलवायु संकट के रूप में देखा जाता है, अब वैश्विक रणनीति और समुद्री व्यापार का नया अध्याय खोल रही है। रूस बदलाव को एक बड़े रणनीतिक और आर्थिक मौके के रूप में देख रहा है।

आर्कटिक महासागर में बर्फ घटने से नॉर्दर्न सी रूट (एनएसआर) के अधिक समय तक खुला रहने की संभावना बढ़ी है, जो यूरोप और एशिया के बीच स्वेज नहर के पारंपरिक रास्ते से काफी छोटा है।

रूस के उत्तरी तट से बैरेंट्स सागर से बेरिंग जलडमरूमध्य तक चलने वाले इस मार्ग की पहुँच पहले मोटी बर्फ के कारण सीमित थी। अब तापमान वृद्धि से गर्मियों में आवाजाही आसान हो रही है। एनएसआर दूरी और यात्रा समय को कम कर सकता है, इससे ईंधन व परिवहन लागत बचेगी। हालांकि, भारी बर्फ, अप्रत्याशित मौसम और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण यह अभी स्वेज नहर का पूर्ण विकल्प नहीं बन सका है। रुस अपनी आर्थिक व रणनीतिक ताकत बढ़ाने का साधन मानता है, जिसके लिए वह बंदरगाहों और परमाणु आइसब्रेकर ग्रुप का विस्तार कर रहा है।

इस भू-राजनीतिक खेल में चीन की भी गहरी रुचि है। खुद को नियर-आर्कटिक स्टेट बताने वाला चीन अपनी पोलर सिल्क रोड योजना से आर्कटिक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। वह रूस के साथ मिलकर इस मार्ग से यूरोप तक सामान पहुँचाने और संवेदनशीलमलक्काजलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने की कोशिश में जुटा है। भारत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत और रूस नॉर्दर्न सी रूट सहयोग पर काम कर रहे हैं, जिसमें चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारे को उत्तरी मार्ग से जोड़ने की संभावनाएँ हैं। यह भारत के लिए ऊर्जा आयात और यूरोप-एशिया के वैकल्पिक समुद्री संपर्क के लिए उपयोगी हो सकता है।

वहीं, अमेरिका के लिए आर्कटिक का बढ़ता महत्व चिंता का विषय है। बेरिंग जलडमरूमध्य के एक ओर रूस और दूसरी ओर अमेरिकी अलास्का होने से यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। यदि रूस और चीन मिलकर गलियारे पर आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव बढ़ाते हैं, तब वैश्विक समुद्री व्यापार के शक्ति संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस प्रकार, आर्कटिक की पिघलती बर्फ केवल पर्यावरणीय बदलाव नहीं, बल्कि व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक महाशक्तियों की रणनीति को प्रभावित करने वाला बड़ा भू-राजनीतिक कारक बन रही है।

नेपाल जैसा भारत में भी ग्लेशियल झीलों से विनाश का खतरा: एनडीएमए

नईदिल्ली। हाल ही में ग्लेशियर फटने से नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद भारत में भी ऐसे ही विनाश की आशंका जताई जा रही है। देश की 40 ग्लेशियल झीलों को संभावित खतरे में बताया है, जिनमें से 7 को अत्यधिक उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। एनडीएमए के मुताबिक, नेपाल-तिब्बत सीमा से सटे भारतीय इलाकों में स्थित ये झीलें कभी भी एक बड़े संकट का कारण बन सकती हैं। नेपाल में हाल ही में हुए ग्लेशियर फटने से 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 4,000 से ज्यादा लापता हो गए थे, जिसने भारत को भी सतर्क कर दिया है। इस भयावह परिदृश्य के मद्देनजर, एनडीएमए ने विशेष रूप से सिक्किम में 40 उच्च-खतरे वाली ग्लेशियल झीलों की पहचान की है, जिनमें से 7 को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इन 40 संवेदनशील झीलों में से 16 का वर्गीकरण हो चुका है, जबकि 13 अभी भी वर्गीकृत नहीं हैं।

अधिकारियों ने बताया कि 16 प्राथमिकता वाली संवेदनशील झीलों में से 13 का विस्तृत वैज्ञानिक आकलन किया गया है। इनमें से अधिकांश झीलें लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इस संभावित आपदा से बचाव के लिए सिक्किम राज्य ने कई महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तावित किए हैं। सिक्किम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव संदीप तांबे ने बताया कि हालिया आकलन में झीलों की गहराई, पानी की मात्रा, मोरेन की मजबूती और हिमस्खलन व भूस्खलन से होने वाले खतरों की जांच की गई है। प्रमुख उपायों में शाको चू झील में सोलर-पावर्ड पंपों का उपयोग करके जल स्तर को 20 से 40 मीटर तक कम करना शामिल है, जिससे लगभग 80 लाख घन मीटर पानी निकाला जाएगा।

दूसरा प्रस्ताव साउथ-नॉर्थ लोनाक क्लस्टर के लिए है, जहाँ डोलमा संपांग में लगभग 24 किलोमीटर नीचे एक पत्थर-चिनाई वाली रोक संरचना का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि संभावित बाढ़ के बल को कम किया जा सके। तीसरा प्रस्ताव गुरुदोंगमार झील परिसर के लिए है, जहाँ अधिकारी मोरेन प्लग पर एक सुरक्षा दीवार बनाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि पवित्र झील को नुकसान पहुंचाए बिना पानी के निकलने को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा, सिक्किम अपने रियल-टाइम निगरानी और पूर्व-चेतावनी सिस्टम का विस्तार भी कर रहा है। शाको चू, केरांग और डोलमा संपांग में स्वचालित निगरानी स्टेशन पहले से ही कार्यरत हैं, और अधिकारी डॉप्लर वेदर रडार लगाने के लिए जगहों की तलाश कर रहे हैं। राज्य में 400 से अधिक ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें से फिलहाल 16 को अत्यधिक संवेदनशील बताया गया है। यह नवीनतम आकलन अक्टूबर 2023 में हुई भीषण ग्लेशियल झील आउटबर्स्ट बाढ़ के बाद आया है।

अल नीनो ने बढ़ाई चिंता

इस साल आखिरी महीने में और बढ़ सकता है प्रभाव

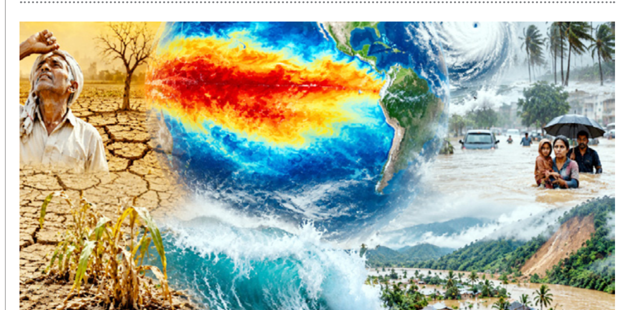

नई दिल्ली। इस साल दुनिया के कई हिस्सों में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। भीषण गर्मी, हीटवेव, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब मौसम विशेषज्ञों के बीच प्रशांत महासागर में मजबूत हो रहे अल नीनो को लेकर चिंता है। आशंका जताई जा रही है कि साल के आखिरी महीनों में इसका प्रभाव और तेज हो सकता है और फरवरी 2027 तक मौसम के असामान्य हालात बने रह सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक अल नीनो उस स्थिति को कहा जाता है, जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसका प्रभाव दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के तापमान, बारिश और मौसमी गतिविधियों पर पड़ता है। इस बार समुद्र के तापमान में हो रही बढ़ोतरी ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। अल नीनो 3.4 सूचकांक से जुड़े आंकड़ों में जुलाई में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा बताया। बाद की साप्ताहिक रीडिंग में यह अंतर बढ़कर करीब 2.2 से 2.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र की गहराई में भी असामान्य गर्मी दर्ज की गई है। जुलाई और अगस्त में प्रशांत महासागर के कुछ गहरे हिस्सों में पानी का तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के अंदर जमा यह अतिरिक्त गर्मी अल नीनो को और मजबूत कर सकती है। इसी वजह से इसके संभावित प्रभाव को बेहद गंभीर माना जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से जारी आकलनों के मुताबिक अल नीनो की स्थिति के फरवरी 2027 तक बने रहने की संभावना है। इसके 2026 के अंत तक मजबूत होने की आशंका जताई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी बढ़ते वैश्विक तापमान और चरम मौसम की घटनाओं को लेकर चिंता जता चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र के बढ़ते तापमान के साथ दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। भारत के लिए अल नीनो विशेष चिंता का विषय है। मजबूत अल नीनो का असर भारतीय मानसून पर पड़ सकता है, जिससे बारिश कमजोर या अनियमित होने का खतरा रहता है। इसका सीधा असर कृषि, जल संसाधनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि, अल नीनो का हर बार भारत के मानसून पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता और अन्य मौसमी कारक भी अहम भूमिका निभाते हैं। सर्दियों को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। अल नीनो वैश्विक तापमान और मौसमी पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत में इस बार सर्दी आएगी ही नहीं।

ट्रंप की धमकी के बाद सुर्खियों में पिकैक्स माउंटेन

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने की सीधी धमकी दी है, जिससे तेहरान में हड़कंप मच गया है। ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी सेना बहुत जल्द ईरान के इस महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमला कर सकती है। हालांकि एक ओर ट्रंप ईरान के साथ इस संघर्ष को युद्ध मानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार हमले की धमकियाँ दे रहे हैं। उनके इस बयान के बाद, ईरान पर अमेरिकी बंकर बस्टर्स बमों के इस्तेमाल का डर एक बार फिर गहरा गया है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है।

अब सवाल यह है कि आखिर यह पिकैक्स माउंटेन क्या है, जिसे ट्रंप ने उड़ाने की धमकी दी है? यह जगह इतनी खास क्यों है? और अमेरिका के लिए इसे निशाना बनाना इतना मुश्किल क्यों माना जा रहा है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सितंबर को कहा कि अमेरिका ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर बहुत जल्द हमला कर सकता है। यह वही जगह है, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा माना जाता है और यह तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दक्षिण में, नतांज परमाणु परिसर के पास स्थित एक पहाड़ी इलाका है। इसे ईरान का सबसे रहस्यमयी और मजबूत अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाना भी माना जाता है, जो नतांज परमाणु परिसर से केवल करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। भले ही अमेरिकी हमलों में ईरान की नतांज यूरेनियम संवर्धन साइट को भारी नुकसान पहुंचा हो, मगर इसी के पास मौजूद पिकैक्स माउंटेन का बाल भी बांका नहीं हुआ है। पिकैक्स यानी कुदाल या चट्टान तोड़ने वाला औजार होता है, इसी वजह से इसे पिकैक्स माउंटेन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1600 मीटर है, लेकिन यह कोई सामान्य पहाड़ी नहीं है। इसके अंदर, जमीन के काफी नीचे सुरंगों का एक बड़ा परिसर बनाया गया है। मौजूद जानकारी और सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि यहाँ कई सुरंग परिसर हैं, जिनमें चार सुरंगों के मुहाने हैं। माना जाता है कि ये सुरंगें पहाड़ के अंदर बने एक बड़े भूमिगत परिसर तक जाती हैं। यह पूरा ढांचा जमीन से कम से कम 100 मीटर नीचे होने का अनुमान है, और इसी असाधारण गहराई की वजह से यह जगह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

आखिर यहाँ बनाया क्या जा रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। पिकैक्स माउंटेन का संबंध ईरान के परमाणु कार्यक्रम से है और अमेरिका लंबे समय से इस जगह पर पैनी नजर रख रहा है। उसका मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यहीं से संचालित हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यहाँ निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था। उस समय ईरान ने बताया था कि पहाड़ के अंदर बनाए जा रहे हॉल का इस्तेमाल उन्नत सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीनें होती हैं, जिनका उपयोग यूरेनियम को समृद्ध करने की प्रक्रिया में किया जाता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि पिकैक्स माउंटेन पूरी तरह चालू हो चुका है या नहीं। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर विशेषज्ञों का आकलन है कि यहाँ निर्माण जारी है, लेकिन यह परिसर अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने हालांकि जुलाई 2026 में दावा किया था कि पिकैक्स माउंटेन में कोई परमाणु गतिविधि नहीं चल रही है।

ईरान ने अमेरिका का किया बुरा हाल

अब ट्रंप की नजर जापान के मोगामी क्साल युद्धपोत पर

वाशिंगटन। ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध अमेरिकी नौसेना काफी दबाव में है। इसी के चलते ट्रंप को साउथ चाइना सी से अपना युद्धपोत हटाना पड़ा था, लेकिन अमेरिकी नौसेना को फिर से ताकतवर बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प कदम उठा रहे हैं।

अमेरिका तीन विदेशी युद्धपोतों को शामिल करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसमें सबसे आगे नाम जापान के मोगामी क्लास का लिया जा रहा है। मोगामी क्लास एक मिनी युद्धपोत है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प द्वारा जारी किए गए एक विशेष आदेश के तहत नौसेना इस अध्ययन को अंजाम दे रही है। इस योजना को फिनलैंड मॉडल का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत शुरूआत में दो युद्धपोतों का निर्माण विदेशी शिपयार्डों में सीधे तौर पर किया जाएगा ताकि उन्हें जल्द से जल्द नौसेना में शामिल किया जा सके। इसके बाद आगे के जहाजों के निर्माण की कमान अमेरिकी शिपयार्डों को सौंप दी जाएगी ताकि देश का घरेलू जहाज निर्माण उद्योग भी दोबारा खड़ा हो सके।

मोगामी की सबसे बड़ी पहचान इसका अनोखा और आधुनिक बाहरी ढांचा है। इस 133 मीटर लंबे और करीब 3900 टन वजनी जहाज को इस तरह से तराशा गया है। इसमें सीधी या खड़ी सतहें बहुत कम हैं। इस खास डिजाइन का मकसद दुश्मन के रडार को भ्रमित करना और अपनी मौजूदगी को लगभग छिपाए रखना है। इससे दुश्मन के लिए इस पर सही टारगेट पर हमला करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

आमतौर पर इतने बड़े युद्धपोतों को चलाने के लिए सैकड़ों नौसैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन मोगामी को महज 90 लोगों का क्रू आसानी से चला सकता है। पानी के नीचे छिपे खतरों को ढूंढ निकालने में मोगामी का कोई मुकाबला नहीं है। इसके पास एडवांस सोनार तकनीक, टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जो समुद्र के सन्नाटे में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर तबाह कर देते हैं। इतना ही नहीं, यह जहाज पानी में बिछाई गई खतरनाक बारूदी सुरंगों को खोजने के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल भी कर सकता है।

दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए मोगामी के आगे एक 127 मिमी की विशाल नौसैनिक गन लगी है, जो तटीय और समुद्री ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है। दुश्मन के जहाजों को डुबोने के लिए इसमें 8 घातक टाइप-17 एंटी-शिप मिसाइलें तैनात हैं। वहीं, हवा से आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए सीरैम डिफेंस सिस्टम और 16 सेल वाला वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगाया गया है।

इस समय अमेरिकी नौसेना अपने युद्धपोतों की संख्या तेजी से बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके अपने घरेलू शिपयार्ड इतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मोगामी फ्रिगेट का कम क्रू, आधुनिक डिजाइन, कम लागत और पहले से तैयार उत्पादन क्षमता अमेरिका के लिए एक मुफीद विकल्प बन चुका है। अगर अमेरिका इसे अपनाता है, तो वह अपने रडार और कॉम्बैट सिस्टम के हिसाब से इस जापानी डिजाइन में बदलाव करके इसे अपने बेड़े में शामिल कर सकता है।

भारत विकास के साथ रोजगार भी बना रहा -पीएम मोदी

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में बोले

नई दिल्ली। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉलेज की 100 वर्षों की यात्रा और देश की प्रगति पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी संस्थान का 100 वर्ष पूरे करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यह यात्रा उपलब्धियों, अनुभवों और प्रेरणाओं का महासागर होती है। उन्होंने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने अपनी 100 वर्षों की यात्रा में कई पीढ़ियों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संस्थान की शुरूआत दरियागंज के एक छोटे से स्थान से हुई थी और आज यह एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसने अनेक पीढ़ियों को अपनी छांव दी है। उन्होंने कॉलेज के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां से कई कलाकार, नेता और वकील निकले हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में पहचान बनाई। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का भी जिक्र किया और कहा कि वे भी इसी संस्थान के छात्र रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2013 के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स संबोधन को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे तत्कालीन केंद्र सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उस मंच से देश के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा था और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विकास कर रहा है और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है।

जेएनयू प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप, 10 छात्राओं की शिकायत पर आईसीसी की जांच शुरू

नई दिल्ली। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में कम से कम 10 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतों का दायरा और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को विस्तृत जांच सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार, शिकायतों की शुरूआत करीब एक महीने पहले एक छात्रा द्वारा की गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ छात्र भी सामने आए और उन्होंने भी उसी प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि प्रोफेसर ने कुछ छात्रों को कैंपस स्थित अपने सरकारी आवास पर बैठकों के बहाने बुलाया और वहां कथित तौर पर आपत्तिजनक व अनुचित यौन व्यवहार की कोशिश की।

नासा ने किया रोमन स्पेस टेलिस्कोप को अंतरिक्ष में रवाना

वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी नई अंतरिक्ष वेधशाला नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप को अंतरिक्ष में रवाना कर दिया है। यह रोमन टेलिस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अंतरिक्ष में मौजूद अनदेखी दुनिया की तलाश करेगा। करीब 4.3 अरब डॉलर की लागत से तैयार यह बस के आकार का टेलिस्कोप पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज प्वाइंट-2 यानी एल-2 की ओर बढ़ रहा है। इसी क्षेत्र में जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप भी ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है। इसे स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया।

रोमन का उद्देश्य जेम्स वेब या हबल की तरह केवल चुनिंदा खगोलीय पिंडों की बेहद विस्तृत तस्वीरें लेना नहीं है।

इसे ब्रह्मांड के बहुत बड़े हिस्से का तेजी से सर्वे करने के लिए तैयार किया गया है। इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल स्पेस टेलिस्कोप से 100 गुना से भी अधिक बड़ा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, जिस क्षेत्र के सर्वे में हबल को करीब एक सदी लग सकती है, रोमन उसी काम को लगभग एक महीने में पूरा कर सकता है। एल-2 तक पहुंचने में टेलिस्कोप को तीन महीने से अधिक समय लग सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल अरबों खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए करेंगे। मिशन के दौरान दो अरब से अधिक आकाशगंगाओं का अध्ययन कर ब्रह्मांड का विशाल त्रिआयामी नक्शा तैयार करने की योजना है।

शिक्षक दिवस: उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य और सेवाओं के लिए राज्यपाल ने किया 68 शिक्षकों का सम्मान

रायपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम् में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह वर्ष-2026 का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका ने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य और सेवाओं के लिए प्रदेश के 68 शिक्षकों का सम्मान किया.

कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि 5 सितम्बर देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं. आज जितने भी राष्ट्र के निर्माता शिक्षक-शिक्षिका को मैं बधाई देता हूं. प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है. नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे देश में हुए हैं.

उन्होंने कहा कि हमारे देश में शिक्षा का महत्व रहा है. हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि शिक्षा के बिना मूलमंत्र अधूरा है. किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, तो शिक्षा जरूरी है. पिछले 2-3 साल में शिक्षा के किए हमने काफी काम किया है. हमारी सरकार में आते ही पता चला कि 200 से ज्यादा स्कूल शिक्षक विहीन हैं. इसके लिए हमने युक्तियुक्तकरण लागू किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय बोली-भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं.

न्योता भोज कार्यक्रम हमने शुरू किया है. जन भागीदारी हम स्कूल में बढ़ा रहे हैं. 341 स्कूलों का पीएमश्री में चयन होगा. उसका भी हम लोग अच्छे शिक्षा के तहत शिक्षा की बढ़ावा देंगे. उन्होंने कहा कि प्राध्यापक, शिक्षकों और प्रोफेसर का प्रमोशन रुका था, उसे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं.

शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाला नहीं, बल्कि पीढ़ी का निर्माता: रामविचार नेताम

रायपुर। कृषि विकास एवं कल्याण, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि राष्ट्र के भविष्य निर्माण में गुरुजनों का योगदान अमूल्य है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के चरित्र और सोच का निर्माता होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप जिले में युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयास विद्यालय तथा नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। शिक्षक ही समाज और राष्ट्र की भावी पीढ़ी के सच्चे निर्माता होते हैं, जो ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के जीवन को आकार देते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम भवन में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं कल्याण, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम रहे। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य, अनुशासन और अच्छे संस्कार भी विकसित करते हैं । वे बच्चों में स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और कुछ नया सीखने की जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं।

ताजा खबर
संक्षिप्त

विष्णु भैया के संबल से सुरक्षित मातृत्व की ओर बिंदु की नई राह

रायपुर। मातृत्व के दौरान महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं बेहतर देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे गर्भावस्था और प्रसव के बाद मां एवं बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंड्राकला निवासी श्रीमती बिंदु मानिकपुरी के लिए भी यह योजना मातृत्व काल में आर्थिक संबल का माध्यम बनी। उनके पति श्री गुलशन कुमार मानिकपुरी कृषि कार्य करते हैं। परिवार की सीमित आर्थिक स्थिति के बीच गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली सहायता ने परिवार को राहत प्रदान की।

अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने सरगुजा जिले में लग रही 'आवास चौपाल'

रायपुर। अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने सरगुजा जिले में लग रही 'आवास चौपाल' अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने सरगुजा जिले में लग रही 'आवास चौपाल' अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने सरगुजा जिले में लग रही 'आवास चौपाल' अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने सरगुजा जिले में लग रही 'आवास चौपाल' प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सरगुजा जिले में अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल की जा रही है। जिले के सभी 7 जनपद पंचायतों की उन ग्राम पंचायतों में, जहां अपेक्षाकृत अधिक आवास अपूर्ण हैं, 'आवास चौपाल' आयोजित कर हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। चौपाल के माध्यम से हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उन्हें आवास निर्माण शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आवास चौपाल में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंच, अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों के हितग्राही, बिहान समूह की दीदियां तथा स्थानीय राजमिस्त्री शामिल हो रहे हैं। चौपाल में अधिकारियों द्वारा प्रत्येक हितग्राही से आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जा रही है तथा निर्माण कार्य में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों की पहचान की जा रही है।

दो दिन पहले ट्रैक्टर से सुकमा पहुंचे ग्रामीण, दो दिन बाद बाइक से गांव पहुंचे कलेक्टर :सीईओ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो तथा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही सुनिश्चित किया जाए। इसी मंशा के अनुरूप सुकमा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए मेटागुड़ा गांव पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मेटागुड़ा गांव के ग्रामीण दो दिन पहले स्कूल, आंगनबाड़ी भवन सहित विभिन्न मांगों को लेकर ट्रैक्टर से जिला मुख्यालय सुकमा पहुंचे थे। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद कलेक्टर श्री अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुंद ठाकुर सहित प्रशासनिक अमला शुक्रवार को किस्ताराम से करीब 20 किलोमीटर दूर पालाचलमा पंचायत के मेटागुड़ा गांव पहुंचा। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ ने बाइक से गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं जानीं और मौके पर ही उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। गांव पहुंचने पर कलेक्टर श्री अमित कुमार एवं अधिकारियों ने पेड़ के नीचे ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। कलेक्टर ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और एक-एक कर उनकी मांगों की जानकारी ली। इस दौरान मेटागुड़ा में आंगनबाड़ी भवन तथा आमापेंटा में प्राथमिक शाला भवन के निर्माण के लिए तत्काल स्वीकृति आदेश जारी किए गए। ग्रामीणों ने गांव में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अपनी अपेक्षाओं से प्रशासन को अवगत कराया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अपने गुरुजनों को सम्मानित कर उप मुख्यमंत्री ने लिया आशीर्वाद

सीएम शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह 2026 में जिले के 108 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से किया सम्मानित

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का समाज में स्थान सदैव आदरणीय और अग्रणी है. विजय शर्मा आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कवर्धा में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण, शिक्षा सत्र 2026-27, शिक्षा दूत और ज्ञानदीप पुरस्कार सम्मान समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 108 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया. सम्मानित शिक्षकों में सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल रहे. उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया और उनके योगदान के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सम्मानित सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य विद्यार्थियों और समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुजनों से मिले संस्कार और ज्ञान को आज भी प्रासंगिक और उपयोगी बताया. उन्होने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. शिक्षक केवल कक्षा में पाठ्यक्रम का ज्ञान देने तक सीमित नहीं होते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और उनके जीवन को सही दिशा देने का कार्य भी करते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है. कक्षा में दिया गया ज्ञान और गुरुजनों द्वारा सिखाए

गए संस्कार जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर काम आते हैं. कार्यक्रम में इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, मोतीराम चंद्रवंशी, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चंद्रवंशी, नगर पालिका उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, लोकचन्द साहू, मनीराम साहू, राजा टाटिया, विजय लक्ष्मी तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण विद्यार्थी उपस्थित रहे.

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने स्वामी करपात्री जी विद्यालय में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कहा कि विद्यालय में गुरुजनों ने पढ़ाई के साथ-साथ खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी बहुत कुछ सिखाया. गुरुजनों द्वारा उस समय पढ़ाया और सिखाया गया ज्ञान आज भी उनके जीवन में उपयोगी साबित हो रहा है. उन्होंने कहा कि बचपन में गुरुजनों के साथ बिताए गए वे पल आज भी उनके लिए महत्वपूर्ण, प्रेरणादायी एवं चीरस्मरणीय बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहें हैं.कार्यक्रम के दौरान भावुक क्षण भी देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने अपने विद्यार्थी जीवन के गुरुजनों जी.आर. चंदेल, पी.पी. दुबे, एम.आर. महोबिया, विजेंद्र श्रीवास्तव और एम.के. गुप्ता का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया. उन्होंने अपने गुरुजनों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु का स्थान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है. गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा, संस्कार और मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन की मजबूत नींव तैयार करते हैं.

84 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा

उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 84 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें से 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा स्थापित की जा चुकी है, जबकि शेष 34 स्कूलों में भी जल्द ही स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है.

मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से कांकेर जिले के 24 शिक्षक सम्मानित

रायपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला पंचायत कांकेर में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के 24 शिक्षकों को उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनमें प्राथमिक शालाओं के 21 शिक्षकों को शिक्षा दूत पुरस्कार तथा माध्यमिक शालाओं के 03 शिक्षकों को ज्ञानदीप पुरस्कार प्रदान किया गया। शिक्षा दूत पुरस्कार के लिए जिले के प्रत्येक विकासखंड से 03-03 शिक्षकों का विकासखंड स्तर पर चयन किया गया था। इसी प्रकार ज्ञानदीप पुरस्कार के लिए माध्यमिक शाला के 03 शिक्षकों का जिला स्तर पर चयन किया गया। शिक्षा दूत पुरस्कार से सम्मानित प्रत्येक शिक्षक को 5 हजार रुपये तथा ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित प्रत्येक शिक्षक को 7 हजार रुपये की नगद पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र मोमेन्टो प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 24 शिक्षकों को सम्मानित करते हुए 1 लाख 26 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कांकेर श्री आशाराम नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से सम्मानित होना शिक्षकों के लिए गौरव की बात है। शिक्षक बच्चों को गढ़ने का काम करते हैं और आज के कार्यक्रम में बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षक भी सम्मानित शिक्षकों से प्रेरणा लें और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए निरंतर समर्पण के साथ कार्य करें। विधायक श्री नेताम ने कहा कि विद्यार्थी अपने शिक्षक को हमेशा याद रखते हैं। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, इसलिए शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनका उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए। शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर देते हुए विधायक श्री नेताम ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे सामान्य परिवारों से आते हैं। उन्हें बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारा जा सकता है।

दूरवर्ती जिलों में जल्द खुलेंगे पीडब्ल्यूडी के सेतु उप संभागीय कार्यालय

रायपुर। सड़कों, भवनों और पुल-पुलियों के कार्यों में गति लाने तथा इनके निर्माण कार्यों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने लोक निर्माण विभाग दूरस्थ क्षेत्रों में भी कार्यालय शुरू कर रहा है। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के 16 उप संभागीय, दो संभागीय और एक सेतु मंडल कार्यालय के साथ ही इन कार्यालयों के लिए सेटअप की मंजूरी दे दी है। इनमें से ज्यादातर कार्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। इनकी स्थापना से निर्माण कार्यों में तेजी के साथ ही विभागीय कामकाज में कसावट आएगी। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र के अंतर्गत 9 नए कार्यालयों की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें जगदलपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय, रायपुर में कार्यपालन अभियंता कार्यालय सेतु संभाग क्रमांक-2, तथा बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, बालोद, मुंगेली, सारंगढ़ और बैकुंठपुर में अनुविभागीय अधिकारी (सेतु उप संभाग) कार्यालय शामिल हैं।

10 नवीन कार्यालय भी मंजूर

राज्य शासन ने भवन एवं सड़क निर्माण के लिए 10 नवीन कार्यालय भी मंजूर किए हैं। इनमें बैकुंठपुर में कार्यपालन अभियंता (कोरिया संभाग) कार्यालय तथा फरसगांव, ओरछा, डोंगरगांव, डौंडी, धमधा, आरंग, खड़गवां, सोनहत और बलौदाबाजार में अनुविभागीय अधिकारी (उप संभाग) कार्यालय शामिल हैं।

थदड़ी के महापर्व पर आरू साहू के सुआ गीत पर सिंधी समाज की महिलाओं ने किया सुआ नाच

रायपुर। सिंधु संस्कार सेवा समिति की महिला विंग द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी थदड़ी महापर्व के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन महादेव घाट, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम माँ संतोषी माता मांदर वाली के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका आरू साहू रहीं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी अमरचंदानी, मनीष पंजवानी एवं देवानंद शर्मा जी मंच पर आसीन रहे। सिंधी समाज के घरों में कल नहीं जला था चूल्हा- सिंधी समाज में थदड़ी पर्व का विशेष महत्व है। धर्म अध्यात्म सामग्री इस दिन शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है

और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। यह परंपरा माता शीतला को समर्पित है और परिवार की सुख-समृद्धि व स्वास्थ्य के लिए मनाई जाती है। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने नशा मुक्त भारत के विषय पर अपने प्रेरणादायक विचार रखे। समिति द्वारा समाज में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों हेतु समिति की अध्यक्ष डिंपल शर्मा को ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में अमरचंदानी जी ने कहा कि सिंधु संस्कार सेवा समिति निरंतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दे रही है। मनीष पंजवानी जी ने सभी को थदड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। अनिल कृष्णानी एव ओम भाटिया द्वारा प्रस्तुत सिंधी गीतों पर महिलाएं झूम उठीं। थदड़ी के महापर्व पर छत्तीसगढ़ी लोक गायिका आरू साहू के सुआ गीत पर सिंधी समाज की महिलाओं ने जमकर सुआ नृत्य किया, जिसने कार्यक्रम में चार चाँद लगा दिए। साथ ही नौका ज्वेलर्स द्वारा मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया जिसमें विजेता महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 महिलाओं की उपस्थिति रही। मंच का सफल संचालन राम खटवानी एवं जया जीवनानी ने किया। कार्यक्रम के समापन के पश्चात महिला मंडल द्वारा काली माता मंदिर में माता रानी को चुनरी एवं श्रृंगार अर्पित किया गया तथा खारुन नदी की महा आरती कर नदी को चुनरी एवं श्रृंगार चढ़ाया गया।

तिल्दा के सगुनी में विकास कार्यों की सौगात, मंत्री टंक राम वर्मा ने किया लोकार्पण

बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और अधोसंरचना के विस्तार से संवर रहा ग्रामीण अंचल

रायपुर। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने आज रायपुर जिला के तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम सगुनी में विकास और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम में नव निर्मित रंगमंच और अमृत सरोवर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों का सम्मान और महिलाओं को पूरक आहार का वितरण किया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नया आयाम देते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की गति को तेज कर दिया गया है।मंत्री श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि बलौदाबाजार विधानसभा के लगभग 260 गांवों और 2 नगरपालिकाओं में विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। विकास कार्यों का आवंटन बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है, ताकि हर पंचायत और गांव को इसका समान लाभ मिल सके। प्रत्येक गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं की पहुंच प्राथमिकता के

17 सितंबर को विकसित भारत के संकल्प के साथ विशेष आयोजन

मंत्री टंकराम वर्मा ने 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से दीप प्रज्वलित कर इसे धूमधाम से मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था एवं आंगनबाड़ियों का सुदृढ़ीकरणग्रामीण बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर अधोसंरचना सुधार जारी है। तिल्दा ब्लॉक के 40 स्कूलों में अतिरिक्त कमरों तथा आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूलों में पेयजल, बाउंड्री वॉल और शौचालयों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों और सामुदायिक शेड के निर्माण को प्राथमिक सूची में शामिल किया गया है।

गांवों का कायाकल्प और अधोसंरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान

ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अधोसंरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधानसभा के 50 गांवों में नई लाइटें लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर जारी कर दी गई है। गांवों में मुक्तिधाम निर्माण, तालाबों का सौंदर्यकरण और पिंडा-बूतरा निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं।राजस्व विभाग के माध्यम से लगभग 15 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिससे ग्रामीण अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी।

सरकार प्रदेश के युवा छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति संवेदनशील: उच्च शिक्षा मंत्री

रायपुर। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ रहे हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बेहद संवेदनशील और बड़ा निर्णय लिया है। प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के एक-दो प्रश्नपत्रों (पेपर्स) में असफल होने के कारण 5वें सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित हो रहे छात्रों को अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम प्रवेश देने की घोषणा की है। इस फैसले से हजारों छात्रों का शैक्षणिक वर्ष (।बंकमउपब ल्मंत) खराब होने से बच जाएगा। मामले की गंभीरता और युवाओं के हित को सर्वोपरि रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि छम्च् के क्रियान्वयन में आ रही किसी भी व्यावहारिक अड़चन को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग और हमारी सरकार प्रदेश के युवा छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। राज्य में नई शिक्षा नीति (हृश्वक्क)को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। इसे लागू करने की प्रक्रिया में यदि कोई भी व्यावहारिक समस्या या व्यवधान उत्पन्न

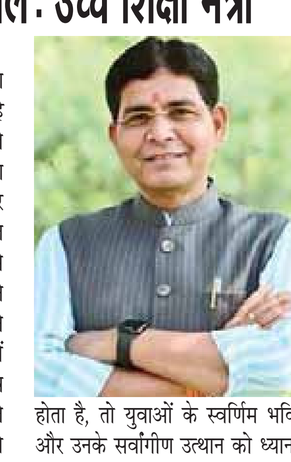

होता है, तो युवाओं के स्वर्णिम भविष्य और उनके सर्वांगीण उत्थान को ध्यान में रखकर उसका त्वरित समाधान निकाला जाएगा। इसी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो छात्र प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के एक या दो पेपर्स में अनुत्तीर्ण होने की वजह से 5 वें सेमेस्टर में दाखिला नहीं ले पा रहे थे, उन्हें अब 5 वें सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए संबंधित अध्यादेश में समय रहते आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। सरकार प्रदेश के सभी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की मंगलकामना करती है।

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, 8.4 ओवर में लक्ष्य हासिल

दुबई। विमेंस एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है। दुबई में खेले गए ग्रुप-ए के मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम महज 55 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम ने 56 रन के छोटे लक्ष्य को सिर्फ 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारतीय गेंदबाजों ने शुरूआत से ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर दबाव बनाए रखा। भारतीय स्पिनरों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 और शेफाली वर्मा ने 1 विकेट लिया। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान की पूरी पारी 55 रन पर सिमट गई, जो महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे कम स्कोर बताया जा रहा है।

56 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरूआत में कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने विजयी रन छक्के के साथ पूरा किया और भारत को शानदार जीत दिलाई।

इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा कायम रखा है। मुकाबले में भारतीय स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। वहीं, पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही।

अयूब-किओंग की जोड़ी को हराकर सात्विक-चिराग चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे

शेनझेन (चीन)। भारत के सात्विकसराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जोड़ी ने शनिवार को भी टूनार्मेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मलेशिया के नूर मोहम्मद अजीरन अयूब और टैन बी किओंग की जोड़ी के खिलाफ जीत दर्ज कर चाइना मास्टर्स के पुरुष युगल के फाइनल में जगह बना ली है।

आज यहां खेले गये सेमीफाइनल में बैडमिंटन रैंकिंग में पांचवें पायदान पर मौजूद भारत की सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर मोहम्मद अजीरन अयूब और टैन वी किओंग की जोड़ी को एक घंटे छह मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 18-21, 21-11 से हराकर चाइना मास्टर्स के फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ सात्विक और चिराग पिछले चार संस्करणों में तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे हैं। वे 2023 और 2025 में रनर-अप रहे थे और 2024 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। एशियाई खेलों के मौजूदा पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियन के पास अब अपना पहला चाइना मास्टर्स खिताब जीतने का एक और मौका होगा। 2005 में शुरू हुए इस टूनार्मेंट को अब तक किसी भी भारतीय शटलर ने नहीं जीता है।

मलेशियाई जोड़ी ने शुरूआती गेम में 5-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन सात्विक और चिराग ने लगातार सात अंक जीतकर वापसी की और मिड-गेम इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 17-15 के स्कोर से आगे बढ़ते हुए अगले पांच में से चार अंक जीतकर पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भी मलेशियाई खिलाड़ियों ने तेज शुरूआत की और 4-0 की बढ़त बना ली, लेकिन फिर सात्विक और चिराग ने अपनी लय हासिल की और 10-8 से आगे हो गए। इसके बाद बढ़त कई बार बदली और दोनों जोड़ियां 18-18 के स्कोर पर बराबरी पर आ गईं। हालांकि, नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी किओंग ने लगातार तीन अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम (डिसाइडर) तक पहुंचा दिया। सात्विक और चिराग ने यह सुनिश्चित किया कि निर्णायक गेम में मलेशियाई खिलाड़ियों की तेज शुरूआत वाली रणनीति दोबारा न चल पाए। उन्होंने शुरूआत से ही नियंत्रण बनाए रखा और मिड-गेम इंटरवल तक 11-4 की बढ़त हासिल कर ली।

साइड बदलने के बाद भी भारतीय जोड़ी ने खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और निर्णायक गेम जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह सात्विक और चिराग का 2026 का तीसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल होगा। मई में थाईलैंड ओपन में वे रनर-अप रहे थे और उसी महीने बाद में सिंगापुर ओपन जीता था। रविवार को होने वाले फाइनल में भारतीय जोड़ी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर अपने करियर का 10वां खिताब जीतने की कोशिश करेगी। पिछले महीने नई दिल्ली में क्वार्टर-फाइनल से बाहर होने के कारण तीसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने से चूकने वाली भारतीय जोड़ी, रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले में दूसरे सेमीफाइनल के विजेताओं का सामना करेगी। यह सेमी-फाइनल मलेशिया के टी काई वुन और याप रॉय किंग तथा चीन के हे जिटिंग और रेन जियांग्यु के बीच खेला जाएगा।

क्रिकेटरों के लिए अलग होटल की व्यवस्था नहीं

टोक्यो। जापान में होने वाले एशियन गेम्स के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भारतीय ओलंपिक संघ अलग से होटल की व्यवस्था नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई आयोजकों की ओर से तय होटलों के बजाय अपनी पसंद का होटल चुनता है, तो खिलाड़ियों के ठहरने, खाने, स्थानीय परिवहन और मैच वेन्यू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बोर्ड की होगी। आईओए के सीईओ रघुराम अय्यर ने कहा कि एशियन गेम्स में शामिल सभी 36 खेलों के खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। बीसीसीआई सीईओ हेमांग अमीन और आईओई सीईओ रघुराम अय्यर के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। बीसीसीआई अगले हफ्ते की शुरूआत में एक एडवांस्ड टीम जापान भेजेगा।

यह टीम होटल, क्रिकेट वेन्यू और दूसरी स्थानीय सुविधाओं का जायजा लेगी। इसके बाद बोर्ड तय करेगा कि आयोजकों की ओर से दिए गए होटलों में रहना है या अपनी व्यवस्था करनी है। अय्यर ने कहा कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के हित में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर बोर्ड अलग व्यवस्था करता है तो आईओए को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी बीसीसीआई की होगी। एशियन गेम्स के आयोजकों ने भारतीय मेंस टीम के लिए थ्री स्टार होटल नागोया एकिमाए और वूमंस टीम के लिए 4-स्टार ग्रैंड होटल की व्यवस्था की है। दोनों होटलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों के आमतौर पर रहने वाले फाइव स्टार होटल की तुलना में ये एक लेवल नीचे हैं।

झारखंड को स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी आज खेल विभाग में कर रहीं सफाई

सुनीता थ्रोबॉल और वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही

रांची। झारखंड के लिए खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुनीता की मौजूदा जिंदगी की कहानी खेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कभी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग-अलग प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली सुनीता आज रांची के मोराबादी स्थित खेल एवं युवा कार्य निदेशालय में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हैं। उन्हें इस काम के लिए हर महीने करीब 10 हजार रुपए मिलते हैं। सुनीता के मुताबिक, वह पिछले 8 से 9 वर्षों से खेल निदेशालय के परिसर में झाड़ू-पोंछा लगाने का काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता। आठ घंटे की मेहनत के बाद मिलने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और घर की बुनियादी जरूरतों में खर्च हो जाता है। सुनीता थ्रोबॉल और वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने झारखंड के लिए दो स्वर्ण और एक रजत पदक समेत कई पदक जीते। उन्होंने तमिलनाडु और राजस्थान में आयोजित प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बावजूद खेल विभाग की ओर से उन्हें ऐसी स्थायी नौकरी या सहायता नहीं मिली, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो सके।

सरकारी खर्च से बने स्विमिंग पूल पर प्राइवेट एजेंसी का नियंत्रण, महंगे शुल्क में फंसी राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा

इंदौर। इंदौर शहर में राष्ट्रीय तैराकी व गोताखोरी चैंपियनशिप होना है। आयोजन के लिए शासन द्वारा वर्ल्ड कप चौराहा पर निर्मित अंतरराष्ट्रीय स्तर का तैराकी स्टेडियम है। निर्माण के दौरान प्रचारित किया गया था कि यहां से ओलिंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं होंगी।

तरणताल को संचालन के नाम पर निजी हाथों में सौंपने के बाद अब न तो खिलाड़ियों की सुध ली जा रही है और न ही स्पर्धाएं ही हो पा रही हैं। राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए लाखों रुपये के शुल्क की मांग की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों की बेरुखी से संभावना है कि राष्ट्रीय स्तर का यह प्रतिष्ठित आयोजन इंदौर से छिन जाए।

स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) द्वारा इंदौर को 42वीं सब-जूनियर एवं 52वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप-2026 (वाटर पोलो एवं डाइविंग) की मेजबानी सौंपी गई है। स्पर्धा का आयोजन सात से 12 सितंबर तक होना है। प्रतियोगिता में डाइविंग एवं वाटर पोलो की स्पर्धाएं भी आयोजित होंगी। वाटर पोलो स्पर्धा के लिए प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी शामिल होते हैं। प्रतियोगिता में देशभर से वाटर पोलो की टीमें आ रही हैं। इस तरह पानी में होने वाले विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं एक साथ इंदौर में आयोजित होंगी। इसमें बड़ी संख्या में देशभर से खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी हिस्सा लेने शहर आएंगे।

शेफाली वर्मा को आउट कर फातिमा सना ने दिखाई अकड़

पाकिस्तानी कप्तान के सेलिब्रेशन पर बढ़ा विवाद

नई दिल्ली। शनिवार, 3 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इतिहास ने पाकिस्तान को कोई राहत नहीं दी। उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हाथों लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में टीम इंडिया ने एकतरफा जीत हासिल की। 55 रनों पर पाक को समेटने के बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए।

पाकिस्तान की कप्तानी फातिमा सना ने जोरदार वापसी की और शेफाली को 12 रनों पर आउट कर दिया। हालांकि, 56 रनों के लक्ष्य के जवाब में शेफाली ने भारतीय टीम को तेज शुरूआत दिला दी। फातिमा ने शेफाली को आउट करने के बाद उनकी तरफ इशारा किया, जिसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही है। शेफाली ने 6 गेंदों पर एक चौके और उतने ही छक्के की मदद से 12 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि वे जल्द से जल्द मैच को समाप्त करना चाहती हैं। हालांकि, पाकिस्तान की फातिमा सना ने वापसी की और उन्हें अपना शिकार बनाया। 22 वर्षीय को आउट करने के बाद सना ने उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए इशारा किया, जिससे पाकिस्तानी कप्तान को फैंस सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ रहे हैं।

कारोबार

कबाड़ से बिजनेस शुरू कर दुनिया में छाया, आज 43500 करोड़ का मालिक; महिलाओं-बच्चों को दान करेगा 75% दौलत

नई दिल्ली। दुनिया में अमीर बनने के बाद लोग अक्सर अपनी दौलत को बढ़ाते रहना चाहते हैं और उसे अगली पीढ़ियों के लिए बचाने की योजना बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे अलग सोचते हैं। इनमें वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल शामिल हैं।

कबाड़ के कारोबार से शुरू करके अरबों डॉलर का कारोबारी साम्राज्य बनाने वाले अग्रवाल ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने का एलान किया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का 75 फीसदी हिस्सा सामाजिक कार्यों और जनकल्याण के लिए देने का संकल्प लिया था। उन्होंने इसी साल की शुरूआत में ये बात कही थी।

इनके जीवन में आएगा बदलाव

अनिल अग्रवाल मानते रहे हैं कि कारोबार से कमाई गई संपत्ति पर सिर्फ परिवार का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा समाज में लगना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 75 फीसदी संपत्ति सामाजिक कार्यों के लिए देने का संकल्प लिया। इससे गरीबों और जरूरतमंदों की जिंदगी में बदलाव आएगा।

किन कामों में इस्तेमाल?

जनवरी 2026 में अपने बेटे अग्निवेश अग्रवाल के निधन के

बाद अनिल अग्रवाल ने इस संकल्प को दोहराया था। उन्होंने कहा कि परिवार का सपना था कि देश में कोई बच्चा भूखा न सोए, किसी बच्चे की शिक्षा आर्थिक कमजोरी के कारण न रुके, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले और युवाओं के पास सम्मानजनक रोजगार हो। अग्रवाल ने संकेत दिया कि अब उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इन्हीं सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में लगाया जाएगा।

बच्चों और महिलाओं पर फोकस

अनिल अग्रवाल के परोपकारी कार्यों का फोकस शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण रहा है। उनका प्रमुख प्रोजेक्ट नंद घर देश के आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की पहल है। इन केंद्रों के जरिए बच्चों को बेहतर पोषण और शुरूआती शिक्षा देने के साथ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उनका मानना है कि भारत का भविष्य मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों और महिलाओं में निवेश जरूरी है।

अनिल अग्रवाल की कहानी

अनिल अग्रवाल की कहानी संघर्ष से सफलता और अब सफलता से समाज सेवा की ओर है। बिहार के पटना से निकलकर उन्होंने छोटे स्तर पर स्क्रैप कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे वेदांता जैसे ग्लोबल कारोबारी ग्रुप की नींव रखी।

आज वह अपनी संपत्ति को निजी उपलब्धि से ज्यादा सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं। 75 फीसदी दौलत दान करने का उनका फैसला भारतीय उद्योग जगत के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि असली विरासत केवल कंपनियां और संपत्ति नहीं, बल्कि वह बदलाव है जो इंसान अपने संसाधनों से समाज में पैदा करता है।

व्यापार और कॉरपोरेट जगत

बायजू से जुड़ी के-3 एजुकेशन की संपत्तियों की नीलामी पर रोक, क्या है मामला?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबी एजुटेक कंपनी बायजू से जुड़ी के-3 एजुकेशन की संपत्तियों की नीलामी पर रोक लगा दी है।

के-3 एजुकेशन बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (टीएलपीएल) की सहायक कंपनी है। कंपनी पर लगभग 150 करोड़ रुपये मूल्य की अपनी संपत्तियों को मात्र 16 करोड़ रुपये में बेचने के आरोप थे। यह आदेश के3 एजुकेशन के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) और क्रिटिकल सॉल्यूशंस की ओर से दायर उस याचिका पर आया है, जिसमें स्वामित्व के सत्यापन तक संपत्तियों की सुरक्षा की मांग की गई थी। न्यायाधिकरण ने कंपनी को संपत्तियों के निपटान पर आगामी 21 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

टाटा टेक्नोलॉजी के पूर्व सीईओ ने बेचे 165 करोड़ के शेयर

टाटा टेक्नोलॉजीज के पूर्व सीईओ एवं प्रबंध निदेशक पैट्रिक रेमन मैकगोल्ड्रिक ने बीएसई पर खुले सौदे के जरिये लगभग 165 करोड़ रुपये के शेयर बेचकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। मैकगोल्ड्रिक ने शुक्रवार को चार चरणों में 21 लाख शेयर बेचे। ये शेयर पुणे स्थित वैश्विक उत्पाद इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा कंपनी में 0.51 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयर 785 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर बेचे गए, जिससे लेनदेन का कुल मूल्य 164.85 करोड़ रुपये रहा। शेयर बिक्री के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज में मैकगोल्ड्रिक की हिस्सेदारी 1.13 प्रतिशत से घटकर 0.62 फीसदी रह गई।

नाडियाडवाला ग्रैंडसन का 8.26 लाख का ऑफिस सौदा

मुंबई : रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रियल एस्टेट एनालिटिक्स फर्म उफ्ए मैट्रिक्स के डेटा के अनुसार, फिल्म निमार्ता कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंधेरी वेस्ट स्थित अपनी ऑफिस प्रॉपर्टी को लीज पर दिया है। यह ऑफिस स्पेस रिया एंड दीया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को 8.26 लाख रुपये प्रति माह के किराए पर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, यह लीज एग्रीमेंट 1 सितंबर 2026 को रजिस्टर किया गया है। इसमें अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड के पास स्थित लोटस ग्रैंड्योर बिल्डिंग की आठवीं मंजिल पर मौजूद ऑफिस नंबर 803 और 804 शामिल हैं।

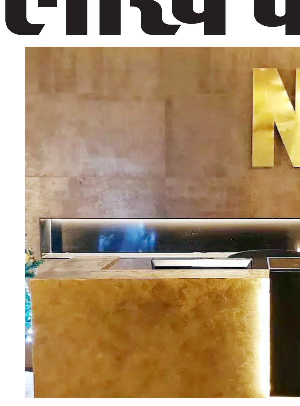

इस लीज की अवधि 28 महीने तय की गई है। एग्रीमेंट के अनुसार, किराए और लीज की शुरूआत 1 अगस्त 2026 से मानी जाएगी। रियल एस्टेट क्षेत्र में इस तरह के बड़े ऑफिस सौदों को मुंबई के कमर्शियल प्रॉपर्टी बाजार की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। अंधेरी वेस्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग अंधेरी वेस्ट मुंबई का एक प्रमुख कमर्शियल और एंटरटेनमेंट हब माना जाता है। यहां फिल्म, मीडिया, प्रोडक्शन और कॉर्पोरेट कंपनियों के कई कार्यालय मौजूद हैं। वीरा देसाई रोड क्षेत्र विशेष रूप से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है।

इस इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी और कॉर्पोरेट सुविधाओं के कारण ऑफिस स्पेस की मांग लगातार बनी रहती है। ऐसे में नाडियाडवाला ग्रैंडसन की प्रॉपर्टी का लीज पर जाना भी बाजार में बढ़ती गतिविधियों का संकेत माना जा रहा है। 28 महीने का हुआ समझौता उफ्ए मैट्रिक्स के आंकड़ों के अनुसार, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और रिया एंड दीया एंटरप्राइजेज के बीच हुए समझौते की अवधि 28 महीने है। इस दौरान किराएदार कंपनी को तय शर्तों के अनुसार ऑफिस स्पेस का उपयोग करने का अधिकार मिलेगा।

कंपनी के पास मुंबई में कई व्यावसायिक संपत्तियां और कार्यालय सुविधाएं होने की जानकारी है। समय-समय पर रियल एस्टेट बाजार में इससे जुड़े सौदों की खबरें सामने आती रहती हैं। मुंबई में बढ़ रहा है ऑफिस लीज बाजार मुंबई में कमर्शियल ऑफिस स्पेस की मांग लगातार बनी हुई है। खासकर अंधेरी, बांद्रा, लोअर परेल और बीकेसी जैसे इलाकों में कंपनियां प्रीमियम ऑफिस स्पेस को प्राथमिकता देती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कंपनियां अब ऐसे स्थानों को चुन रही हैं जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन सुविधा और कारोबारी माहौल उपलब्ध हो। यही कारण है कि मुंबई के प्रमुख इलाकों में ऑफिस लीजिंग गतिविधियां तेज बनी हुई हैं।

रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े सौदों पर नजर रियल एस्टेट एनालिटिक्स कंपनियां लगातार बड़े प्रॉपर्टी सौदों पर नजर रखती हैं और उनके आंकड़े बाजार के रुझान को समझने में मदद करते हैं। नाडियाडवाला ग्रैंडसन की यह लीज भी मुंबई के प्रीमियम ऑफिस मार्केट में एक महत्वपूर्ण सौदे के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल इस समझौते के बाद अंधेरी वेस्ट के कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार में गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। आने वाले समय में मुंबई में ऐसे और बड़े ऑफिस लीज सौदे सामने आने की संभावना है।

सफाई के बाद हवा में भी नंबर-1 बनने की ओर इंदौर

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान

इंदौर। स्वच्छता के सिरमौर इंदौर ने अब अपनी आबोहवा को शुद्ध रखने में भी एक नया मुकाम हासिल किया है। 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026' में इंदौर ने देश के शीर्ष तीन शहरों में अपनी जगह पक्की कर ली है। सूत्रों की मानें तो इस प्रतिष्ठित सर्वेक्षण में शहर ने दूसरा पायदान हासिल किया है। हालांकि, रैंकिंग की आधिकारिक और अंतिम घोषणा 7 सितंबर को नई दिल्ली में की जाएगी। इस खास उपलब्धि के लिए इंदौर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना है।

दिल्ली में मिलेगा 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सराहना पुरस्कार'

सात सितंबर को नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन के गंगा ऑडिटोरियम में 'स्वच्छ वायु दिवस' कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव परिणामों की विधिवत घोषणा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान इंदौर को 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सराहना पुरस्कार' से नवाजा जाएगा। यह सम्मान ग्रहण करने के लिए शहर के महापौर और निगमायुक्त को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी इस पुरस्कार की सूचना पहुंच चुकी है। वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने जमीनी स्तर पर कई अहम कदम उठाए, जिनका सीधा और सकारात्मक असर इस सर्वेक्षण में नजर आया।

निगम के प्रमुख प्रयास इस प्रकार रहे

वर्तमान में नगर निगम के सूत्रों के हवाले से इंदौर के दूसरे स्थान पर रहने की सुगबुगाहट है। हालांकि, शहर की वास्तविक रैंकिंग और स्थिति की अंतिम तस्वीर 7 सितंबर को दिल्ली के मुख्य समारोह में ही स्पष्ट होगी, जब परिणामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

सिंहस्थ 2028 के लिए रेलवे का मेगा प्लान, चलेंगी 125 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

सुरक्षा में तैनात होंगे अक्वाले स्मार्ट कैमरे : स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने पर काम

उज्जैन। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सिंहस्थ के दौरान देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे 125 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रविवार को इंदौर पहुंचकर रेलवे की तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि यात्रियों को यात्रा के लिए ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़े। चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर स्टेशन, शास्त्री ब्रिज और आसपास चल रहे रेलवे से जुड़े विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियोंसेस्टेशनरीडेवलपमेंट, यात्री सुविधाओं और इंदौर से जुड़े महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इंदौर-मनमाड़, इंदौर-खंडवा और इंदौर-उज्जैन रेल सेक्शन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सिंहस्थ 2028 में करोड़ों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए रेलवे ने अभी से यात्री परिवहन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि सिंहस्थ के दौरान 125 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों के जरिए उज्जैन के साथ इंदौर और आसपास के शहरों को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रेलवे का प्रयास होगा कि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा मिल सके। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ यात्रियों पर अतिरिक्त किराए का बोझ न पड़े, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा।

इंदौर से अलग-अलग शहरों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने की मांग पर भी रेलवे काम कर रहा है। चेयरमैन ने कहा कि इंदौर से संचालित होने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया जारी है। इससे इंदौर के यात्रियों को नियमित रेल कनेक्टिविटी मिलने के साथ सिंहस्थ के दौरान भी यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

इंदौरस्टेशनकेरीडेवलपमेंट में तेजी के निर्देश

रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जून 2025 में भी उन्होंने स्टेशन का रिव्यू किया था। उस समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्टेशन के विकास और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे और क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, इस पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि स्टेशन के विकास की पूरी रूपरेखा जनरल मैनेजर और उनकी टीम के साथ साझा की गई है। इसे रेलवे बोर्ड के स्तर पर भी प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि यात्री सुविधाओं को बेहतर करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।

शास्त्री ब्रिज का निरीक्षण, नए रेलवे ओवरब्रिज पर भी चर्चा

सतीश कुमार ने इंदौर के शास्त्री ब्रिज का भी निरीक्षण किया। ब्रिज के कारण यातायात और भविष्य में बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, उसके दौरान वैकल्पिक यातायात व्यवस्था बेहद जरूरी होगी। नए एलाइनमेंट को लेकर दिए गए सुझावों पर भी रेलवे गंभीरता से विचार कर रहा है।

नए शास्त्री रेलवे ओवरब्रिज के शुरूआती दौर का काम जल्द शुरू करने की दिशा में काम किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) तकनीक वाले कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों के जरिए स्टेशन परिसर में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। नई तकनीक से लैस कैमरों में चेहरे की पहचान और स्कैनिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। इससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और सुरक्षा एजेंसियों को समय पर अलर्ट करने में मदद मिल सकती है। रेलवे परिसरों और ट्रेनों में चूहों की समस्या को लेकर भी चेयरमैन ने अधिकारियों से जानकारी ली। वर्तमान में सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

इंदौर-मनमाड़ और इंदौर-खंडवा रेल प्रोजेक्ट भी अहम

चेयरमैन ने इंदौर से जुड़े महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की। इंदौर-मनमाड़ और इंदौर-खंडवा रेल सेक्शन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इंदौर-उज्जैन सेक्शन की क्षमता और यात्री सुविधाओं से जुड़े कामों को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। सिंहस्थ के दौरान इंदौर से उज्जैन जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इस रेल मार्ग की क्षमता और संचालन व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।

इंदौर के विकास को मिली नई रफ्तार : लोक परिवहन के क्षेत्र में इंदौर को मिली बड़ी सौगात

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में मेट्रो ट्रेन का विस्तार केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि विकास के एक नए अध्याय की शुरूआत है। आज मेट्रो का नया चरण शुरू हुआ है और आने वाले समय में इसके और चरण पूरे होंगे। मेट्रो के माध्यम से इंदौर को उज्जैन और पीथमपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य क्रमश: आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को इंदौर में मेट्रो ट्रेन के नये चरण के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेट्रो के पहले चरण को मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद अब इसका विस्तार शहर के अंदरूनी क्षेत्रों तक हो रहा है। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में मेट्रो इंदौर सहित पूरे मालवा क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को नयी दिशा देगी। इंदौर के मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड द्वारा 2 हजार 850 करोड़ रुपये की लागत से सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर तक मेट्रो कॉरिडोर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने बटन दबाकर मेट्रो का शुभारंभ किया।

विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता- मंत्री श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग को शनिवार को वार्ड क्रमांक 71 एवं 79 में आयोजित विश्व के सबसे बड़े नरेला रक्षाबंधन महोत्सव के चौथे दिन 31 हजार 117 बहनों ने राखी बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में हिंदू, सिख और मुस्लिम सहित अन्य धर्मों और समाजों की बहनों ने राखी बाँधकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ﹰल्ले बहनों ने भी महोत्सव में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। मंत्री श्री सारंग ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में स्नेह और रिश्तों की भावना किसी धर्म या समुदाय की सीमाओं में बंधी नहीं है। उन्होंने कहा कि बहनों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए यह संदेश दिया कि स्नेह और विश्वास का यह बंधन समाज को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है। नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में विभिन्न धर्मों और समाजों की बहनों की एक साथ सहभागिता ने इसी महान भारतीय भावना को साकार किया। अलग-अलग आस्थाओं और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आई बहनों ने एकजुट होकर रक्षासूत्र बांधा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।

बोड़री में युवक की धारदार हथियार से हत्या

बरुहा नदी किनारे खून से लथपथ मिला, शरीर पर मिले निशान

शहडोल

जिले सिंहपुर थाना क्षेत्र के बोड़री गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 18 वर्षीय युवक अविनाश नापित की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई।

युवक बरुहा नदी के किनारे गंभीर हालत में मिला था। परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, अविनाश घर के पास बरुहा नदी के किनारे बैठा था। इसी दौरान उसके पिता वहां से गुजरे। अविनाश ने उनसे कहा कि वह थोड़ी देर बाद घर आ जाएगा। कुछ समय बाद ही एक युवक ने उसके पिता को फोन कर बताया कि अविनाश नदी के पास खून से लथपथ पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही सिंहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

खुलासा नहीं हुआ

मृतक की पहचान सुनील नापित के बेटे अविनाश नापित निवासी अतरिया टोला बोड़री के रूप में हुई है। सिंहपुर थाना प्रभारी एसपी चतुर्वेदी ने बताया कि अज्ञात आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। हत्या किसने और किस वजह से की, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है।

एमपी में पटवारी के नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति मामले में नया मोड़...

हाई कोर्ट ने अभ्यावेदन पर पुनर्विचार करने के दिए निर्देश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सीमित विभागीय परीक्षा में मेरिट सूची में प्रथम स्थान हासिल करने के बावजूद नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति से वंचित रहे एक पटवारी के मामले में सक्षम प्राधिकारी को उसके अभ्यावेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के आपराधिक मामले में बरी होने और समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति दिए जाने के तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए।

प्रमोद कुमार शर्मा वर्तमान में पटवारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा/भर्ती परीक्षा में नायब तहसीलदार पद के लिए भाग लिया था। 30 जून 2018 को आयोजित परीक्षा में उन्होंने 200 में से 152.49 अंक प्राप्त किए और मेरिट सूची में पहले स्थान पर रहे।

हालांकि, उनके खिलाफ भोपाल की अदालत में एक आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण उन्हें नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पहले भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका वर्ष 2019 में खारिज हो गई थी। इसके बाद पुनर्विचार याचिका भी वर्ष 2024 में निरस्त हो गई। मामले में नया मोड़ तब आया, जब नौ अप्रैल 2026 को भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संबंधित आपराधिक मामले में प्रमोद कुमार शर्मा को बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने शासन के समक्ष नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दिया, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि समान परिस्थिति वाले भानु प्रताप सिंह को हाई कोर्ट के आदेश के बाद 30 अप्रैल 2026 को नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति/ पदोन्नति दी जा चुकी है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर नया और विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सक्षम प्राधिकारी को प्रमाणित आदेश प्राप्त होने के दो माह के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभ्यावेदन पर निर्णय लेते समय याचिकाकर्ता के बरी होने और भानु प्रताप सिंह को दिए गए लाभ को ध्यान में रखा जाए।

मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत

कई की हालत गंभीर, जांच में जुटा प्रशासन

सागर। बंडा में शनिवार रात जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार रात में करीब दर्जनभर लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बंडा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम बंडा अस्पताल में कराया जा रहा है। गंभीर हालत वाले पांच मरीजों को उपचार के लिए बीएमसी सागर भेजा गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बंडा पहुंचे। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कराई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बंडा में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

इनकी हुई मौत

पुलिस के अनुसार मृतकों में गोलू उर्फ चमन लोधी (45), निवासी गूगरा खुर्द, दिग्विजय लोधी (28), निवासी नौराज, करतार सिंह लोधी (30), निवासी नौराज, उजियार सिंह लोधी (56), निवासी गूगरा खुर्द, रोशन लोधी (30), निवासी पाटन थाना विनायका और राजेंद्र लोधी (32), निवासी नौराज-गूगरा शामिल हैं। गोलू उर्फ चमन को पहले से कैंसर की शिकायत होने की जानकारी भी सामने आई है।

पांच मरीज बीएमसी रेफर

हरनाम राय (42), निवासी चौका, उत्तम नत्थू नायक (42), निवासी दलपतपुर, मंगल रजक (40), निवासी गूगरा खुर्द, परम आदिवासी, निवासी हिनौता और धनसिंह आदिवासी (30), निवासी हिनौता को गंभीर हालत में बीएमसी सागर रेफर किया गया है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने शिक्षक दिवस पर मध्यप्रदेश के 6 शिक्षकों को किया सम्मानित

भोपाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर आवर्ड-2026 के अंतर्गत आयोजित समारोह में देशभर के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। मध्यप्रदेश के शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले छह शिक्षकों एवं शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में डॉ. अर्चना शुक्ला, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सुश्री संगीता यादव, प्रो. सौरव दत्ता, श्रीमती रीना गुप्ता एवं श्रीमती ज्योतिबाला राठौर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी सम्मानित शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना मध्यप्रदेश के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य का निमार्ता होता है। मध्यप्रदेश के इन शिक्षकों ने अपने नवाचारों, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की उपलब्धियां प्रदेश के अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों को आधुनिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का यह सम्मान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक समुदाय के लिए गर्व का अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के इन 6 शिक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए शिक्षा को समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनाया है। उन्होंने आशा जताई कि इन शिक्षकों की उपलब्धियां प्रदेश के युवा शिक्षकों और विद्यार्थियों को नए प्रयोग करने तथा उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगी। सम्मानित शिक्षकों में डॉ. अर्चना शुक्ला, विज्ञान एवं जीव विज्ञान की शिक्षिका हैं और पिछले 15 वर्षों से परियोजना आधारित शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अनेक अभिनव और कम लागत वाली परियोजनाएं संचालित की हैं। एक हजार से अधिक स्पैरो हाउस की स्थापना, विद्यालय परिसर के वृक्षों की क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल मैपिंग तथा ह्यप्लांट इमोशनह्ल जैसी अभिनव परियोजनाएं उनके उल्लेखनीय कार्यों में शामिल हैं।

महिलाओं से बदसलूकी के आरोपों पर शहडोल जिला पंचायत सख्त, पूजा दीक्षित से प्रभारी पद छीना

शहडोल। जिला पंचायत शहडोल ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने वाली अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। जयसिंहनगर जनपद के गोपालपुर संकुल में पदस्थ सहायक विकासखंड प्रबंधक पूजा एस दीक्षित को विकासखंड प्रबंधक / प्रभारी जयसिंहनगर के दायित्वों से मुक्त करते हुए जिला कार्यालय शहडोल में संलग्न कर दिया गया है।

लिखित शिकायत और वीडियो क्लिप आई थी सामने

जानकारी के अनुसार दीक्षित के खिलाफ महिलाओं को अपमानित करने, डराने-धमकाने, अभद्र व्यवहार करने और भययुक्त वातावरण तैयार करने की लिखित शिकायत और वीडियो क्लिप सामने आई थी। नईदुनिया में प्रकाशित होने के बाद मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति ने इसे गंभीरता से लिया।

जांच के लिए तीन सदस्यीय दल का गठन

आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया है। जांच पूरी होने तक उन्हें जिला कार्यालय में अटैच किया गया है। यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल द्वारा की गई है।

वन विहार में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर हुए कार्यक्रम

भोपाल। संचालक वन विहार श्री विजय कुमार के निर्देशन में आज 5 सितंबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर भोपाल बर्ड्स एवं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आज पक्षी भ्रमण एवं गिद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों एवं प्रकृति प्रेमियों को गिद्धों के महत्व, उनकी पारिस्थितिक भूमिका तथा संरक्षण के प्रति जागरूक करना था।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।